हरियाणाा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 मार्च, 1985

खण्ड 1 अंक 9

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 20 मार्च, 1985

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(9)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर	(9)23
वर्श 1985–86 का बजट पे ा करना	(9)29
वाक आउट	(9)49

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 20 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चंडीगढ़ में 9.30 बजे प्रातः हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उतर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज अब सवाल होगें।

Officials dismissed on account of corruption charges in the Haryana State Agricultural Marketing Board.

***848. Chaudhri Balbir Singh Grewal:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of officials of the Haryana State Agriculture Marketing Board, if any, dismissed from service on account of corruption charges since the inception of the said Board to-date; and

(b) whether any officials, out of those referred to in part (a) above, were reinstated and promoted, if so, the reasons therefore?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) दो।

(ख) जी हां। एक मामले मे उस द्वारा दायर अपील मे सरकार द्वारा रिमांउ पर अध्यिकारी को बहाल किया गया था और बाद मे सक्ष्म प्राधिकारी द्वारा उसकी पदोन्नति के आदे ा को वापिस ले लिया गया था।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने मेरे सवाल के उत्तर मे जवाब दिया है कि स्टेट एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड ने दो आफिसर्ज के खिलाफ कार्यवाही की है। इनमे से एक आफिसर एक्स.ई.एन. साहब है जिन के खिलाफ 34 केसिज कुरप ान के थें। आउट आफ 34 केसिज 33 केसिज प्रूव हो चुके है। इस आफिसर को अक्तुबर महीने मे टर्मिनेअ किया गया था। लेकिन दिसम्बर महीने मे री–इनस्टेट कर दिया गया। क्या मुख्यमंत्री मंत्री महोदय बतायेगे कि जब उनका टर्मिनेटप किया गया था उस के क्या कारण थे और उसको री–इनस्टेट करने के क्या कारण हैं? इसके इलावा एक और एक्स.ई.एन. साहब है जिनके खिलाफ भी सैवरल केसिज है। जहां तक मुझे मालूम है उसके खिलाफ कुरप ान के 25 केसिज है लेकिन उनको सरकार ने सस्पैंड भी नही किया, बल्कि प्रोमोट किया है। इस का क्या कारण है? चीफ मिनिस्टर साहब हाउस मे बार बार यही कहते है कि उनके नोटिस मे जो भी कुरप ान के केसिज आयेगे, वे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि इस अधिकारी के खिलाफ 34 केसिज थे जिन मे से 33 प्रूव हो चुके

है। हम ने बाकायदा इस अधिकारी को सस्पैंड किया, रिवर्ट किया और टर्मिनेट भी किया। इस के बाद इस अध्किारी ने अपील की। अपील के बाद केस को दोबारा रिमांड करना पड़ा क्योकि जितनी फारमैंलिटीज पूरी करनी चाहिए थी, उतनी नही हुई थी। जब उनको दोगारा रिवर्ट किया तो उन्होने हाई कोट मे अपील कर दी। ये हाई कोर्ट मे एक बार नही अध्यक्ष महोदय, कई बार गये हैं। मै सदन को बताना चाहता हूं कि पहले जब बोर्ड ने इसको डिसमिस किया तो ये हाई कोर्ट मे चले गए। हाईकोर्ट ने कहदिया कि गवर्नमैंट की डायरैक ान पर बोर्ड ने इनके खिलाफ एक ान लिया हैं। बोर्ड ने दोबारा केस ऐग्जामिन किया और फेसला किया कि इनको सरकार की डायरैक ान पर नही बल्कि अपने तौर पर डिसमिस किया गया है। फिर वह हाई कोर्ट मे चले गए और वहा से केस जीत गए। अब हम इस आदमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे चले गए है। इस लिए अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि हम इन्कावायरी नही करते यह गलत बात है। जो गड़बड़ करता है इसके खिलाफ हम एक ान लेते है। जहां तक दूसरे एक्स.ई.एन. की बात है, इसका इस केस के साथ कोई ताल्लूक नही है। जैसा कि माननीय सदस्य कहते है कि उस अधिकारी के खिलाफ केसिज है, हम इस केस को दिखवा लेगें और अगर कोई कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेगें।

चौधरी औम प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, ग्रेवाल साहब ने दो एक्स.ई.एन. का जिक्र किया है और कहा है कि एक के खिलाफ

34 केसिज थे और दूसरे के खिलाफ 25 केसिज थे। इसी तरह से एक मामला डिफरैंट मार्किट कमेटीज मे तरपाल खरीदने का था। इस वक्त इन्कवायरी के काफीव केसिज मार्किट कमेटीज के पैंडिंग पड़े है और इन्कवायारी चल रही हैं। बार बार यह पूछा जाता है कि फलां केस का क्या हुआ तो जवाब आता है कि इन्कवायरी हो रही है। स्पीकर साहब, इन्कवायरी मे दस दस साल का पीरियड लग जाता है लेकिन इन्कवायरी पूरी नही होती। इतना पीरियड इस लिए लग जाता है कि जिन आफिसर्ज को इन्कवायरी का काम सौपा जाता है उनके पास पहले ही काफी काम होता है और वे इतनी इन्कवायरी को अटैंड नही कर पातें। इस वक्त बोर्ड के पास इस तरह के काफी मामले विचाराधीन हैं। क्या मुख्यमंत्री महोदया किसी होई रैंक की किसी आफिसर को केवल तरह तरह की इन्कवायरी के लिए मुकरर्र करैगे ताकि वह मार्किट कमेटीज व बोर्ड के केसिज को डील कर के जल्दी रिपोर्ट दे सकें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि पिछली दफा तरपालो की खरीद का मामला हाउस मे आया था। उस वक्त हमने कहा था कि हम बाकायदा इस मामले की तह मे जायेगें। हम बाकायदा तह मे गए और जो एक ान लिया। जिन लोगों का कसूर पाया गया उनके खिलाफ कार्यवाही की है। जो और केसिज है उनकी तह मे भी जाएगें। जिस किसी का भी कसूर होगा, जो भी व्यक्ति दोशी मिलेगा, सरकार उसको मुआफ नही करेगी। जहां तक एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड के दूसरे एक्स.ई.एन.

की बात हे जैसा कि माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था बोर्ड ने इसी एक्स.ई.एन. को और एक अकाउटैट को डिसमिस किया था।

चौधरी औम प्रका ः स्पीकर साहब, बहुत सारे केसिज पैंडिंग है जिन मे इन्कवायरी चल रही हैं। क्या कोई प्रोपोजल सरकार ने अंडर कंसीड्रे ान है कि कंस्ट्रक ान विंग के जितने केसिज है, उनको डील करने के लिए किसी हाई स्टेटस के आफिसर को इन्कवायरी आफिसर मुकरर्र करे ताकि वह आफिसत गहराई मे जाकर इन्कवायरी करके जल्दी से रिपोर्ट दे दें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सीनियर आफिसर ही इस काम मे लगे हुए हैं। जेसा कि मैने पहले कहा कि पूरी इन्कवायरी करेगें, अगर माननीय सदस्य के नोटिस मे ऐसा कोई केस हो कि फलां जगह फलां अधिकारी का फाल्ट है तो हमे बताए, हम जरूर इन्कवायरी करवायेगें। सी.ए. (चीफ एड मिनिस्ट्रैटर) काफी सीनियर आफिसर है और इन्कवायरी का काम नही के अंडर है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि एक्स.ई.एन. हाई कोर्ट मे पहुंच गया और केस जीत गया। क्या मुख्यमंत्री जी बताएगें कि गवर्नमैंट ने अपनी डिफैंस मे जो वकील मुकरर्र किया था कहीं यह वकील दूसरे वकील के साथ तो नही मिल गया था? गवर्नमैंट केस क्यो हारी? क्सा इस के कारण जानने की आप नें कोि ा ा की?

श्री अध्यक्षः यह कोई क्वै चन नही है। (व्यवधान) ये कह रहे है कि सुप्रीम कोर्ट में गए है। तो वकील के साथ मिलने की इस मे क्या बात है?

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मार्किट कमेटीज मे तरपाल खरीदे गए थे। इस खरीद मे काफी गड़बड़ हुई थी ओर ये केसिज मार्किट कमेटीज के सैक्रेटरीज के खिलाफ थे। इन केसजि मे 70–80 लाख रूपये का घपला है। इनकी इन्कावायरी पैंडिंग थी लेकिन इन्कावायरी पैंडिंग होने की बावजूद भी इन सेक्रेटरीज को बहाल कर दिया गया हैं। अब पता लगा है कि बिजिलैंस डिपार्टमैंटने इन्कवायरी कर के रिपोर्ट डिपार्टमैंटल एक ान के लिए भेाज दी है। मै मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सैकेट्रीज सस्पैंउ हुए थे उन मे से कितने डिसमिस हुए है ओर इस केस की लेटेस्ट पोजी ान क्या है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बेसिक सवाल मे कोई ताल्लूक नही रखता, यह सवाल दूसरा है। मार्किट कमेटीहज के नीचे जो सैक्रेटरीज होते है उनके बारे मे सवाल पूछा गया हैं जहां तक विजिलैंस डिपार्टमैंट की रिपोर्ट आने का तालूल्क है, इस रिपोर्ट मे अगर कोई व्यक्ति जरा सा भी कसूरवार पाया गया तो हम उस के खिलाफ हर हालत मे कार्यवाही करेगें।

श्रीमती प्रसन्नी देवीः क्या मुख्य मंत्री जी की नालेज मे यह बात है कि एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड का एस.सी. जो रोहतक

मे पोस्टिड है, वह चार–चार महीनें तक वहा नही जाता। उसके खिलाफ काफी चार्जिज है। रोहतक मे एक माईना गांव है जहां एक सड़क बननी थी। चूंकि यह आफिसर वहां नही मिलता, इसलिए यह सड़क नही बन सकती थी। डी.सी. साहब को तो वे मिलते ही नही और इस बात की ि ाकायत डी.सी. साहब को हमे ाा रहती है। एक दिन सी.एम. साहब रोहतक गए थें। इन्होने वहा पूछा कि एस.सी. साहब कहां है। वे कही नही मिलें। उस दिन उन को सैस्पैंड किया गया था। क्या अब सरकार ने उस एस.ई. को बहाल तो नही कर दिया?

चौधरी भजन लालः आप की बात ठीक है ये वही अफसर है तो उस दिन गैर हाजिर था और उस को सस्पैंड किया था। इस केस मे भी यह अधिकारी हाई कोट मे चला गया हैं। (व्यवधान)

चौधरी नर सिह ढाडाः अध्यक्ष महोदय, मै मुख्यमंत्री जी से जानवना चाहता हूं कि मार्किट कमेटीज के एक एक्स चेयरमैंन के खिलाफ एक केस था, उस केस की लेटेस्ट पोजी ान क्या है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का बेसिक क्वे चन से कोई ताल्लूक नही है।

चौधरी औम प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मूझे जानकारी है ये दोनो अधिकारी एग्रीक्लचर मार्किटिंग बोर्ड के

कंस्ट्रक ान विंग से ताल्लूक रखते है औरी इन के खिलाफ काफी आरोप भी हैं। पब्लिक अंडर टेकिंग कमेटी की रिपोर्ट आठ है इसमे भी इन दोनो अधिकारियों का हवाला हैं। कंसट्रक ान विंग इन अधिकारियों के मातहत है। क्या सरकार इस विंग का काम पी. डब्ल्यू.डी. के हवाल करेगी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मर्किटिंग बोर्ड के पास बहुत ज्यादा काम हैं बल्र्ड बैंक से काफी पैसा आता है। जिसे उसे खर्च करना होताहै। उनके पास अलग स्टाफ भी है। अगर इस काम को पी.डब्ल्यू.डी. को दे देगे तो काम सफर करेगा। काम इतना नही हो पाएगा।

श्री फतेह चन्द विजः अध्यक्ष महोदय, इन्होने जवाब मे फरमाया है कि हाई कोर्ट ने दो दफा यह कहा है कि गवर्नमैंट का सस्पैन ान के आदे ा नही देने चाहिए थें। क्या मुख्यमंत्री जी बताएगें कि आयंदा के लिए कोई निर्णय ले लिया गया है कि कार्पोरे ान या बार्ड के किसी भी कर्मचारी की ससपैन ान आर्डर गवर्नमैंट न देकर के कार्पोरे ान या बोर्ड खुद देगें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि बोर्ड की या कार्पोरे ान की अलाहिदा फंक ानिंग है ओर यदि वहा कोई काम गलत होता है तो उस परवह स्वयं कार्यवाही करेगा या ऐक ान लेगा लेकिन यदि सरकार के नोटिस मे भी कोई गलत बात आ जाए तो सरकार भी डायरैक ान दे सकती है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, मै मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हू कि यदि कमि नर अम्बाला डिविजन और डायरैक्टर विजिलैंस की रिपोर्ट का पब्लिक अन्डरटैकिंगज कमेटी करप् ान के चार्जिज देखनेके लिए मांगती है? दूसरी बात स्पीकर साहब, यह है कि 7–8 साल तक इंक्वायारी पैंडिंग पड़ी रहती हैं रिपोर्ट पे ा ही नही होती। करप् ान के चार्जिज की इंक्वायरी अगर 7–8 साल तक चले तो करप् ान और बढेगी। क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएगें कि इस सम्बन्ध मे वे क्या करना चाहते है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पब्लिक अन्डरटैकिंग कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार पूरी तरह विचार करती हैं। किसी सम्बन्ध मे अगर कमि नर की कोई रिपोर्ट आती है तो उस पर भी सरकार विचार करती है। जिस किसी अधिकारी के खिलाफ करप् ान चार्जिज अगर कमेटी ने साबित किए है या कमि नर ने साबित किए है तो हर हालत मे सरकार उसके खिलाफ कायवाही करेगी।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, मेरे पहले प्र न का जवाब नही आया। मे यह जानना चाहता हूं कि यदि कमि नर की रिपोर्ट को और डाररैक्टर विजिलैंस की रिपोर्ट को पब्लिक अन्डरटैकिंगज कमेटी देखना चाहे तो क्या चीफ ऐडमिनिस्ट्रैटर एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड उन्हे कमेटी को दिखाने से रिफयूज कर सकता है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नही है। वे हाउस को थोड़ा सा मिसलीड कर रहे हैं। इन्होने कहा ाि कि सैक्रैटरी ऐग्रीक्लचर सारी फाईल इन्हे दे दे। उन्होने कहा कि फाईल मे और बाते भी है जो सीक्रेट है। इसलिए सारी फाईल तो हम नही दे सकते लेकिन और कोई जानकारी जिसे आप चाहते है और वह इस केस से ताल्लूक रखती है उसे हम देने के लिए तैयार है तो स्पीकर साहब, मेरा यह निवेदन है कि सारी की सारी फाई माननीय सदस्य को भी नही मांगनी चाहिए क्योकि जब तक किसी ने औथ आफ सीक्रेसी न ली हो तब तक सारी फाईल उन्हे हम दे नही सकतें।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, मैनपे तो एक सवाल पूछा लेकिन इन्होने कहा कि मै हाउस को मिसलीड कर रहा हूं। यह बड़ी गल्त बात है।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। मैने यह फाईल खुद मंगवा रखी है।

Expenditure on Tourism

846 Smt. Chandrawati: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the year wise expenditure incurred on different items including building material, wages etc. relating to Tourism separately during the year 1979-80, 1980-81, 1982-83 and 1983-84; and

(b) whether any norm of per square feet of expenditure on tourism buildings has been prescribed, if so, the details thereof together the per square feet of expenditure actually incurred on the said building?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती हैं (अनुलग्नक–क)

(ख) पर्यटन भवनों के कोई अलग से नोरम निर्धारित नही है। अपितू लोक निर्माण विभाग के नोरम जो 100/– रूपये प्रति वर्ग फुट साधारण बिल्डिंग ओर 110/–रूपये प्रति वर्ग फुट असाधारण बिल्डिंग के है ही हरियाणा पर्यटन निगम ने अपनाया हुआ है। इसी प्रकार बिजली कार्यो के लिए 10 प्रति ात तथा 15 प्रति ात की दर और जन स्वास्थय सेवाओ के लिए 25 प्रति ात अनदरूनी तथा 10 प्रति ात बाहरी बिल्डिग लागत पर लगाये जाते है। इन्ही दरों पर खर्च का हिसाब लगाया जाता है और इसे अनुलग्नक 'क' के आईटम एक पर दिया गया है आगे यह भी स्पश्ट किया जाता है कि कुछ मामलों मे पर्यटन भवनों की दर कुछ उंची होती है क्योकि इनका आर्टिटेक्चरल डिजाईन पर्यटक उधोग की आव यकता अनुसार रखा जाता है। कथित दरों को हाल ही मे बनाये गये पर्यटन भवनों मे भी अपनाया गया है।

अनुलग्नक 'क'

भिन्न–भिन्न मदों जैसे बिल्डिंग सामग्री, बेसिज इत्यादि पर पर्यटन से सम्बन्धित किए गए वार्शिक खर्चो का ब्यौराः–

खर्चे की मुख्य आईटम		वर्श (रूपये लाखो में)				
		1979–80	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84
1	बिल्डिंग सामग्री	64.38	78.64	143.29	315.38	82.64
2	वेजिज	47.43	56.74	65.92	82.23	93.94
3	फर्नीचर और औजार	08.13	16.65	20.17	32.54	30.56
4	प्रचार	03.00	06.59	08.50	08.50	10.00
5	मुरम्मत	20.86	20.71	21.65	26.86	44.32
6	परिवहन सेवाए	–	–	–	13.71	–

नोट	1.	भवनव निर्माण खर्च वास्तव मे समस्त विकास जिसमे भूमि की लागत भवन सामग्री, सड़के, भू–दृ य आदि आते है, भाामिल है। क्योंकि सामग्री के खर्चे के समस्त विकास

		खर्चे से अलग करना सम्भव नही हैं।
	2.	वेजिज के खर्चो मे हरियाणा पर्यटन निगम तथा विभाग से सारी तन्खाह की अदायगियां भाामिल है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कुछेक मामलों मे पर्यटन भवनो की दर कुछ उंची होती हैं। क्या वे बताएगें कि वह दर कितने रूपये प्रति वर्ग फुट ऊंची होती है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक नौमर्ज का ताल्लूक है, मैने अभी बताया कि पी.डबलयू.डी. का नोर्म 100 रूपये प्रति फुट साधारण बिल्डिंग और 110 रूपये प्रति वर्ग फूट असाधारण बिल्डिग का है। टूरिज्म की कई जगह पर 100 रूपये प्रति वर्ग फुट से भी कम आया है। कई जगह यह 94 रूपये 85 पैसे हैं, 86 रूपये 61 पैसे और कई जगह 123 रूपये, 109 रूपये और 125 रूपये भी आया है।

चौधरी ओम प्रका : स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री ने इस प्र न के पार्ट (बी) के जवाब मे कहा है कि टुरीज्म की जो बिल्डिंग है उनका रेट उनके स्पै ाल आर्किटैक्चर डिजाइन वगैरहा की वजह से कुछ ज्यादा है। क्या वे बताएगें कि आर्डिनरी बिल्डिंग के रेट और इन बिल्डिंग के रेट मे कितना फर्क है?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब पहले आ चुका है। आपने खुद भी देखा हागा कि सरकारी दफतर की बिल्डिंग और होटल की बिल्डिंग की चमक दमक मे बहुत फर्क होता है।

श्री देवी दासः क्या मुख्यमंत्री जी बताएगें कि टूरीजम कार्पोरे ान वाले अपनी बिल्डिंग को स्वयं क्यो बनाते है जबकि दूसरी सारी बिल्डिंग को पी.डबलयू.डी. वाले बनाए तो अलग से नौमर्ज तय करने की कोई जरूरत नही पड़ेगी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन बिल्डिंगज के डिजाईन मे थोड़ा फर्क है। आपने भी यह बात अभी बताई है और माननीय सदस्य खुद भी इस बात को जानते है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, पानीपत मे जो स्काई लार्क नामक टूरिजम कम्पलैक्स है उसमे मै भी कभी आते जाते चाय पी लेती हूं। मैने वहां देखा है कि मैटीरियल बहुत बिलो स्टैंडर्ड लगाया गया है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात की जांच करवायेगें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होने आज ही यह बात बताई है अगर वाक्या ही ऐसी बात है तो आज ही मै चैक करवा दूंगा। अगर मैटीरियल ठीक नही पाया गया तो जिस अधिकारी या ठेकेदार का कसूर मिलेगे उसके खिलाफ ऐक ान लिया जाएगा।

Uniform for Harijan Girl Students

***814 Prof. Sampat Singh:** Will the minister of State for Education be pleased to state the amount, if any, sanctioned by Haryana Government for the purchage of cloth for making uniforms for Harijan Girl Student in the State during the year 1982-83, 1983-84 and 1984-85 (to date) together with the amount actually spent separately?

Minister of State For Education (Sh. Jagdish Nehra): The amount sanctioned and spent durin the said period (to-date) for teh purchase of uniform cloth for schduled Caste Girl Student is as under:-

Year	Amount sanctioned (Rs. in Lakhs)	Amount spent (Rs. in Lakhs)
1982-83	17.52	6.72
1983-84	37.62	3.87
1984-85 (Up to 08-03-1985)	62.21	57.69

प्रो. सम्पत सिहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि स्कूल मे पढने वाली हरिजन लड़कियों के लिए सन् 1982–83 मे 17.52 लाख रूपये सैक ान किए गए थे लेकिन खर्च केवल 6.72 लाख रूपये हुए। इसी तरह से सन् 1983–84 मे सैक ान हुए 37.62 लाख रूपये और खर्च हुए 3.87 लाख रूपये। स्पीकर साहब, मै जानना चाहता हूं कि गरीब बच्चियों के लिए जब इतने रूपये सैक ान हुए तो वह पूरे खर्च क्यो नही किए गए?

एक बात इनसे मै और जानना चाहता हूं। क्या यह कपड़ा इसलिए तो नही खरीदा गया कि खरीदते वक्त इनका तालमेल नही बैठ पाया हो या जो कुछ सौदा तय होना था वह न हो पाया हो? साथ ही ये यह भी बता दे कि यह जो कपड़ा लिया है यह किन किन फमर्ज से लिया है और किस रेट पर लिया हैं।

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पता नही क्या बात हो गई है जो ये इस तरह की बाते करते है? भाायद इनको अपना जमाना याद आ रहा है। (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिहः अध्यक्ष महोदय, ये मेरे सवाल का जवाब दें।

श्री जगदी ा नेहराः आप जैसा सवाल करेगे वैसा ही जवाब आएगा। सवाल ठीक करेगें तो जवाब भी ठीक आएगा। आपने जिस ढंग से सवाल किया है उसी ढंग से मै जवाब दे रहा हूं। (विघ्न) सारे हरियाणा को पता है कि आपने क्या क्या कार्यवाही की है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः प्रो. सम्पत सिह जी आपने तो सप्लीमैंटरी किया था वह कलियर था। आप इसे डायरैक्ट, स्ट्रैट–वे पूछ लेते तो अच्छा था लेकिन आपने इतना चढा चढा कर पूछ लिया जिस कारण से उन्होने यह जवाब दिया। (विघ्न)

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, यह बात स्पश्ट है कि सन् 1982–83 मे 17.52 लाख की बजाए 6.72 लाख रूपये

खर्च हुए। उसका कारण यह है कि सन् 1981–82 मे डिस्ट्रिक्ट लैवल पर परचेज हुआ करती थी लेकिन सन् 1982–83 मे सैन्ट्रल लैवल पर हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई और यह फेसला किया गया कि भविश्य मे परचेज यह कमेटी करेगी। इस कमेटी के चेयरमैंन मुख्यमंत्री जी है। स्पीकर साहब, सितम्बर के महीने मे परचेज के आर्डर दिये गयें। जब उस कपड़े की इनसपैक ान हुई तो वह सबस्टैन्डर्ड मिला इसलिए वह खरीदी गया। उसके बाद टाईम नही था कि टैन्डश्र मंगाये जाये और आर्डर प्लेस किया जायें। सन् 1982–83 मे आर्द ा डाईंग एन्ड पूफिंग वर्कस अम्बाला कैन्ट की फर्म थी जिसे आर्डर प्लेस किये गये थें। सन् 1983–84 मे अक्तुबर मे आर्ड प्लेस कर दिये गये थे लेकिन जब स्पैसिफिके ान की बात आई तो हम ठीक नही थी। यह फर्म मैसर्ज सूमेर चन्द, दिल्ली की थी। फिर हमने सन् 1983–84 मे दुबारा से कानपुर टैक्सटाईलव मिल, कानपुरव को आर्डर प्लेस किया और बार बार उन्हे रिमाइन्ड भी कराया गया कि आप अपनी दो परसैन्ट सिक्योरिटी जमा कराये लेकिन उन्होने सिक्योरिटी जमा नही कराई। आर्डर प्लेस करने से पूर्व हम दो परसैन्ट सिक्योरिटी जमा करवाते हैं। जब उन्होने सिक्योरिटी जमा नही कराई तो आखिर मे हाई पावर्ड कमेटी की मिटिंग हुई और फेसला किया गया कि अब परचेज नही हो सकती। क्योकि अगर दुबारा टैन्डर इन्वाईट करेगे तो देर लगेगी। सन् 1983–84 के अन्त का फेसला है कि एजुके ान डिपार्टमैंट पहली क्लास से 11वी क्लास तक की लड़कियों के नाम दे दें, उन्हे कपड़ा दे दिया जायेगा।

स्पीकर साहब, सन् 1984–85 मे 62.21 लाख रूपये का प्रावधान किया है जिस मे से 57.69 लाख रूपए का कपड़ा आ चुका है और तकरीबन पांच लाख का कपड़ा 30 मार्च तक आ जायेगा।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि पहले तो हर साल डिस्ट्रिक्ट पर परचेज होती थी। अब फेसला किया है कि मुख्यमंत्री जी ने अन्डर कोई हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई है तो हैड क्वार्टर पर परचेज करती है। स्पीकर साहब, सरकार चाहे कितनी भी कोि ज्ञ ा कर ले लेकिन परचेज मे कही न कही डिले हो जाती है और नीचे के लैवल पर गड़बड़ हो जाती है। मै आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब इन्होने नम्बर आफ हरिजन गर्ल्ज स्टुडैन्टस का पता कर लिया है तो उस हिसाब से अमाउन्ट तय करके उन्हे पैसा क्यो नही दे देतें?

श्री अध्यक्षः पैसे का मिसयुज होगा।

श्री जगदी ा नेहराः जैसा कि सुरेन्द सिह जी ने कहा कि सैन्ट्रेलाईजे ान की वजह से देर होती हैं बात उनकी दूरूस्त है। देर होती है लेकिन उसमे बचत भी काफी होती है। सन् 1984–85 का फेसला इसी साल के भाुय मे हो गया। अध्यक्ष महोदय, मै बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के लैवल पर जो कमेटी बनी हुई है। उसमे यह फेसला हुआ हे कि एक लड़की का चार मीटर दिया जाए और वह पचास रूपये तक का कपडऋा होना चाहिए। हमे यहां पर कपड़ा खरीदने से फायदा यह हुआ

कि जो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता मे फेसला हुआ उस कारण 38 या 36 रूपये मे कपड़ा मिल गया। एक लड़की के कपड़े 14–15 रूपये की बचत हुई और वह कपड़ा भी अच्छा मिला। इस बारे मे जो डीलिंग वगैरहा होती है वह डायरैक्टर जनवरल सप्लाई एन्ड डिस्पोजल या कन्ट्रोल आफ स्टोर्ज करता है। एजुके ान डिपार्टमैंट केवल स्पोसिफिके ान और पैसा देता हैं।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, वर्दी का मतलब यह होता है कि सिली सिलाई दी जाय लेकिन आम तौर पर कपड़ा देते है। आप जानते है कि आजकल अगर किसी कपड़े को सिलवाते है तो जितनी कपड़े की कीमत है उससे ज्यादा सिलाई लगती है। क्या सरकार की ये हिदायते नही कि सिली सिलाई वर्दी दी जाये या उन्हे सिलाई की कौस्ट दी जायें?

श्री जगदी ा नेहराः सारा कपड़ा चार मीटर दिया जाता है जो सलवार और कमीज के लिए होता हैं। सिलाई के पैसे नही दिये जाते और न ही सिली सिलाई वर्दी दी जाती है।

श्री मनफूल सिहः स्पीकर साहब, मै आपकी मार्फत जानना चाहता हूं कि यह कपड़ा प्राईवेट फर्मो से क्यों खरीदा जाता है और कोआप्रेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर्ज से इसलिये नही खरीदा जाता क्योकि वहा से कमी ान नही मिलता।

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, कोआप्रेटीव कन्ज्यूमर्ज स्टोर्ज मे आठ दस लाख का कपड़ा नही होता। इस बार जो कपड़े को आर्डर प्लेस किया गया है वह ने ानल टैक्साटाईल कार्पोरे ान को किया गया है जो गवर्नमैंट आफ इन्डिया की अन्डर टेकिंग है। 57 लाख की कनसाईनमैंट आ चुकी हैं।

डा. भीम सिंह दहियाः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जवबा दिया है कि सन् 1982–83 मे 11 लाख का कपड़ा नही खरीद सके औरप 1983–84 मे 35 लाख का नही खरीद सके। दोनो सालों मे यह रूपया इन्होने खर्च ही नही किया और जो इन्होने इसका कारण दिया है वह इससे ज्यादा लेम एक्सक्यूज नही हो सकता। It has been callously indifferent to the people. मै आपसे अपील करूंगा कि गवर्नमैंट को सैंसर किया जायें। सवाल यह है कि जो पैसा बचा है वह लैप्स हो गया या एक्यूमूलेट हो गया? क्या इस पैसे को बच्चो के लिए इस्तेमाल करेगें?

श्री जगदी ा नेहराः यह बिल्कूल गल्त है बात है। गवर्नमैंट की तरफ से कोई ऐसी बात नही हुई। एक दफा तो यह हुआ कि स्पेसिफिके ान के मुताबिक कपड़ा ठीक नही निकला। दूसरी दफा दो फर्मो से फाईनल बात की लेकिन उन्होने कपड़ा सप्लाई नही किया। तीसरा इन्होने कहा कि क्या यह एक्यूमुलेट हो गया है। यह पैसा दिया गया है वह पहले से बहुत ज्यादा दिया गया है। पहलें थोड़े बैनिफि ारिज थे, कम लड़कियो को कपड़ा

दिया जाता था लेकिन इस बार एक लाख 25 हजार लड़कियों को कपडा़ दिया गया। मैने स्कूलों मे जा कर चैक भी किया हैं। सब लडकियों को कपड़ा दिया गया हैं। माननीय सदस्य स्कूलों मे जा कर चैक करे कि किस किस स्कूल मे कपड़ा पहुंचा। अगर नही पहुंचा तो हमे बतायें।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए बताया कि सन् 1982–83 मे सितम्बर मे और सन् 1983–84 मे अक्तुबर मे कपड़े का आर्डर प्लेस की गई? पहले आर्डर प्लेस क्यों नही किया गया? इन्होने साथ ही यह भी फरमाया है कि चार मीटर कपड़ा ही देते है तो इस चार मीटर मे दसवीं या ग्याहरवी क्लास की लड़कियों का सूट कैसे बनेगा? कृप्या मंत्री महोदय इस पर रो ानी डालें। दूसरे चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने जो सुझाव दिया है कि सरकार कपडत्रे के चक्कर में क्यों पड़ती है, उन्हें पैसे ही क्यों नही दे देती। उनका सुझाव बेहतरीन हैं। हाई पावर्ड कमेअी बनी हुई है, वह कपड़े का नमूना देखेगी कि कौन सा बढिया है और कौन सा घटिया है और कौन सा स्पैसिफिके ान के मुताबिक हैं? लड़कियों को नकद पैसा दे दिया जाये और यह पाबन्दी लगा दी जाये कि वे ड्रैस पहन कर आयेगी।

10.00 बजें

श्री जगदी ा नेहराः जो बात मानपनीय सदसय ने कही है ऐसी कोई बात नही है। सरकार की तरफ से जो डिपार्टमैट तक बजट पहुंचता है। उसमे टाईम लग जाता है। कई बार पैसे सितम्बर और अक्तुबर तक पहुंचते है। जब तक महकमे के पास बजट पहुंचता है, जनरली उस वक्त तक मई–जून–जुलाई का टाईम हो जाता है और सरकार की तरफ से इसमे कोई देरी की बात भी नही हैं। जहां तक इन्होने यह कहा है कि 4 मीटर कपड़ा कम है ठीक नही है, यह बिल्कुल बच्चियों के लिये ठीक हैं। 4 मीटर कपड़ा काफी कपड़ा होता हैं। लड़कियों के सूट के लिये यह कपड़ा काफी रहता है। जहां तक इन्होने तीसरी बात कही है कि 50 रूपया या जो रूपया भी वर्दी के लिये सैक ान हो, वह नकद दे दिया जायें, सरकार का विचार यह है कि उनको नकद देना नही रहता। दूसरे कई केसिज मे पैसेनकद देने का प्रावधान है जैसे स्कालरि ाप आठवी क्लास के लिये 10 रूपये और 10 वी क्लास के लिये 20 रूपये हर महीने दिये जाते है ओर इसके अलावा लेखन सामग्री के लिये हर साल 5 और 10 रूपये के हिसाब से दिये जाते हें यह जो नकद देने वाली रकम है, यह हरिजन लड़कियों की सुविधा के लिये हरियाणा मे दी जाती हैं। वर्दी का पैसा नकद देना ठीक नही है।

श्री फतेह चन्द विजः ि ाक्षा मंत्री महोदय ने बताया है कि जुलाई–अगस्त में महकमे के पास पैसा ऐलाके ान होकर आता है। मै यह जानना चाहता हूं कि अप्रैल से जुलाई–अगस्त

तक महकमे का काम कैसे चलाते है? इस दौरान महकमे का बिना पैसे के कैसे काम चलता है?

श्री जगदी ा नेहराः मेरे कहने का मकसद यह है कि प्रोसीजरल दिक्कत की वजह से देर हो जाती है।

चौधरी फूल चन्दः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहूँगा कि इन स्कूलो मे जिनमे हरिजन बच्चियों की वर्दी दी जाती है, क्या इनमे दूसरे बच्चों के लिये भी कोई वर्दी निधार्रित है, मगर नही है तो क्या मंत्री जी यह नही समझते कि अगर केवल हरिजन बच्चियां ही एक अलग किस्म की वर्दी पहनेंगी तो वे पिन प्वायंट होगी और इससे उसमे हीन भावना आयेगी। क्या मंत्री महोदय कुछ ऐसा प्रबन्ध करने के लिये तैयार है कि उन बच्चियों मे हीनता की भावना न आये और इसके लिये उनको किसी दुसरे प्रकार से कम्पनसैट किया जायें?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नही है कि इससे हरिजन बच्चियों मे हीनता की भावना आती हों। यह तो उन लोगो को सुविधा या मदद देने की बात है जिनके पास कोई साधन नही है।

चौधरी फूल चन्दः क्या क्लासिज मे दूसरे बच्चों के लिये भी वर्दी है?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, ऐसा नही हैं। जैसे हरिजन बच्चियों को पहली क्लास से लेकर ग्यारहवी क्लास तक वर्दी दी जाती है, वैसे दूसरी लड़कियाां को वर्दी नही दी जाती।

चौधरी कुन्दन लालः स्पीकर साहब, यह बड़ी खु ी की बात है कि हरियाणा सरकार ने यह फेसला किया है कि अभी हरिजन बच्चों के लिये वर्दियां दी जायें। मै आपके द्वारा सरकार से यह विनती करूंगा कि क्या यह सरकार बैकवर्ड क्लासिज के गरीब घरानों के बच्चो को भी वर्दी देने पर विचार करेगी?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात विचाराधीन नही है कि बैकवर्ड क्लासिज की लड़कियों को भी वर्दी दी जायें।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे बताया है कि 4 मीटर कपड़ा लड़कियों के सूट के लिये काफी होता है। अध्यक्ष महोदय, मैने यह काम किया हुआ हैं। दसवी जमात की लड़की के लिये साढे 4 मीटर कपड़े से कम मे सूट तैयार नही होता। अध्यक्ष महोदय, जो बच्ची पहली जमात मे पढती हैं उसके लिये भी चार मीटर कपड़ा और जेा बच्ची चौथी, पांचवी या 10वी जमात मे पढती है उसके लिये भी 4 मीअर कपड़ा दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि जो हरिजन लड़की 10वी जमान मे पढती है उसके लिये कम से कम 5 मीटर कपड़ा होना चाहिये। मेरा इससे मिलता जुलता ही एक सवाल ओर है। इन्होने

अपने जवाब मे यह बताया है कि एक होई–पावर्ड–कमेटी बनी हुई है जो कि मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता मे काम करती है ओर उसकी मार्फत हरिजन लड़कियों के लिये कपड़ा परचेज किया जाता है। * ** * * * ** * ** * * ** * ** * * ** ** *

श्री अध्यक्षः यह बात रिकार्ड मे नही आयेगी।

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि 4 मीटर कपड़े मे लड़कियों का सूट नही बनता या कम पड़ जाता है। मै इन से पूछना चाहता हूं कि क्या ये बतायेगे कि उनके पाजामे –कुर्ते को कितना कपड़ा लगता है? मेरे ख्याल से यह पौने चार मीटर मे बन जाता है। यह कहना कि 4 मीटर कपड़ा लडकियों के सूट के लिये कम है और इसमें सूट तैयार नही होता, गलत बात है। जहां तक इनकी दूसरी बात का ताल्लूक है यह बिल्कूल निराधार है। हाई पावर्ड कमेटी बनने के बाद आज तक, मै अपने ि ाक्षा विभाग की बात ही कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जब भी कोई परचेज की है तेा इससे विभाग का बहुत फायदा हुआ हैं। इस से अच्छी चीज डिपार्टमैंट को कोई मिली नही हैं। जब चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय क्या हालात थी। अध्यक्ष महोदय, दो साल 6 महीने तक चौधरी देवी लाल मुख्यमंत्री रहे और उन्होने हरियाणा मे जो कुर्प ान की हालत पैदा की, वह मेरे ख्याल मे हिन्दूस्तान मे कही भी नही थी। (व्यवधान व भाोर) उस हालत को कोई मुकाबला नही है। (व्यवधान व भाोर) आप जब कहते हो तो हम सुनते है, इसलिए

जब हम कहते है, तो हमे भी सूनों। (व्यवधान व भाोर) उन्होने प्रदे ा का यह भट्ठा बिठा दिया कि वह उठ नही सकता था। (व्यवधान व भाोर)

(इस समय बहुत से सदस्य एक साथ बोलने लग गयें)

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, मै रिक्वैस्अ करूंगा कि जब आप एक बात भाुरू करते हो तो फिर आप मे उसका जवाब सुनने की भी हिम्मत होनी चाहियें। भागी राम जी मै आप को इसलियें थोड़े सप्लीमैंट्रीज पूछने की इजाजत देता हूं कि आप कोई न कोई ऐसी बात कर देते है जिसमे गड़बड़ भाुरू हो जाती हैं।

श्री जगदी ा नेहरा : स्पीकर साहब, हर बार ये चौधरी भजन लाल का नाम लेते है यह कर दिया वह कर दिया, जरा अपने गिरेबान मे भी तो मुंह डाल कर देखे तो पता चल जायेगा कि चौधरी देवी लाल क्या करते रहे है। आप को खुद को पता होगा कि चौधरी देवी लाल ओर उनके लड़के ने क्या क्या काम किये है। (व्यवधान व भाोर) आपका लीडर क्या बहुत अच्छा हैं। चौधरी देवी लाल ने हरियाणा मे क्या–क्या हालात पैदा किये, यह सब को पता है। (व्यवधान व भाोर)

बहिन भाान्ति देवी : स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि चार मीटर मे स्कूल मे पढने वाली छात्राओं की सलवार और कमीज जो वर्दी के लिए चाहिए वह बन जाती है। परन्तु, नौवी

दसवीं, ग्यारहवी कलास मे जो लड़कियां पढती है उनकी चुननी या दुप्पटा भी चाहिए क्योकि हमारी सभयता के अनुसार बड़ी लड़कियों को चुन्नी या दुप्ट्टा औढना चाहिए। क्या मंत्री महोदय बड़ी लड़कियों के लिए चुन्नीयां दुप्ट्टा का भी इन्तजाम करने की कृपा करेगें?

श्री जगदी ा नेहरा : स्पीकर साहब, बहन जी ने जो सुझाव दिया है यह ठीक है ओर नौवी, दसवी और ग्यारहवी क्लास की लड़कियों के लिए अगल से चुन्नी दुप्ट्टा का प्रावधान कर देगें।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, इसमे कोई दो राय नही है कि इस व्यवस्था मे जब कोई परचेज होती हे तो कोई न कोई गड़बड़ होने की सम्भावना हो सकती हैं। स्पीकर साहब, इस मे भी कोई दो राय नही है कि चीफ मिनिस्टर साहब के इतने बिजी होने के कारण उनके लिये यह सम्भव नही है कि वे इस प्रकार की परचेज की देखरेख कर सके। .. . .

श्री अध्यक्षः मैने भी जब इस सवाल का जवाब पढा तब मेरे दिमाग मे भी यह बात आई कि दो साल मे अमाउन्ट तो ज्यादा स्ेक ान हुआ लेकिन खर्चा काफी कम रहा आपने देखा है कि जब मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता मे परचेज भाुरू हुई तो 62 लाख रूपए मे से 8 मार्च तक 57 लाख रूपया खर्च किया गया। यह अमाउन्ट कम तो नही हैै।

श्री हीरा नन्द आर्यः आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा कहना यह है कि अगर इस खरीद फरोख्त मे भ्रप्टाचार को डिसैन्ट्रलाईज कर दिया जाए और नीचे तक काम चलता रहा तो ठीक रहेगां। (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, मेरा एक सुझाव यह भसी है कि वर्दी का कपड़ा खरीद कर देने की बजाय उन लड़कियों को वर्दीवव के पैसे दे दिये जाए और उनको कह दिया जाए कि इस क्लर की वर्दी पहन कर आनी हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि इसमे क्या दिक्कत है?

श्री जगदी ा नेहरा : स्पीकर साहब, अगर कपड़े के पैसे दे दिए जाए तो उससे यह होगा कि एक तरफ का कपड़ा नही खरीदा जा सकेगा और कपड़ा अच्छा भी नही मिलेगा। स्पीकर साहब, जहां तक भ्रश्टाचार को डिसैन्ट्रलाईज करने का मामला है, चौधरी देवी लाल के जमाने मे यह डिसैन्ट्रलाईज था। चोधरी देवी लाल ने इस को डिसैन्ट्रलाइज किया था। उसक वक्त यह चौधरी देवी लाल, उनके लड़के और उनके पोते तीन जगह डिसैन्ट्रलाईज था। चौधरी देवी लाल ******** के काम मे दखल नही देते थे। (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, आप इनको कहे कि ये ठीक ढंग से बात करे। ये गवर्नमैंट की पोलीसीज पर बोलें उन को क्रीटीसाइज करें और कोई अच्छे सुझाव दें। हीरा नन्द आर्य पांय छः बार दल बदल कर भी भ्रश्टाचार की बात करे और चौधरी देवी लाल बीस बार दल बदल कर भ्रश्टाचार की बात करें तो यह कहा तक ठीक है?

श्री अध्यक्षः चौधरी औम प्रका ा का नाम नही आयेगा।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, यह सवाल का कोई जवाब नही है। यह बात ठीक नही है कि किसी पार्टी के लीडर को गाली देना भाुरू कर दें। (व्यवधान व भाोर)

श्री जगदी ा नेहरा : क्या इन्होन ही सब कुछ कहने की ठेकेदारी ले रखी ह? स्पीकर साहब, आप इन को कहे कि ये ठीक ढंगा से बात करें।

मास्टर राम सिंहः स्पीकर साहब, हरिजन बच्चों को यूनिफार्म दी गई है। यह बहुत अच्छी बात है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि हरिजन लड़कियों को जूते और भाल देने का भी प्रावधान किया जायेगा?

श्री जगदी ा नेहरा : जूते और भाल का प्रावधान नही किया जा सकता।

Deaths in Pokice Costody.

***853. Sh. Kitab Singh:** Will the Minister for State for Revenue and Home be pleased to state—

(a) Whether any persons died in police custody in the State during the period from 01-01-1984 to 01-12-1984, if so, the number therefore together with the Causes of their deaths;

(b) if reply to part (a) be in the affirmative, the action, if any, taken against the police officials found responsible for the said deaths; and

(c) Whether any women were murdered or burnt on account of alleged dowry disputes in the State during the period referred to in part (a) above, if so, the details of such cases together with the action, if any, taken thereon?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल) (क, ख और ग): विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पुलिस हिरासत मे मरे हुए व्यक्तियों के मृत्यू का कारण और उनकी मृत्यू के लिए जिम्मेदार ठहराये गए पुलिस कर्मचारियों के विरूद्व की गई कार्यवाही का विवरण।

(क और ख) हां। दिनांक 01.01.1984 से 31.12.1984 की अवधि मे राज्य मे चार व्यक्तियों की कथित रूप से पुलिस हिरासत मे मृत्यू हुई है।

(1) श्री राजबीर पुत्र करतार सिंह निवासी जान्टी कलां, थाना राई तहसील एंव जिला सोनीपत की मृत्यू उसके भारीर के मर्म अंगो पर लगी चोटों के कारण हुई थी। इस सम्बन्ध मे मुकदमा न. 264 तिथी 01.10.1984 धाराधीन 302 भाःदःसः थाना राई मे दर्ज किया गया है। इस मुकदमा मे प्रधान सिपाही प्रताप सिंह और सिपाही श्री निवास को गिरफ्तार किया गया है और

उनके विरूद्व दिनांक 02.01.1985 को न्यायालय मे चालान किया गया है।

(2) बाले पुत्र चन्दन जाति गुज्जर निवासी गांव अतमादपुरर थाना एनःआईःटीः फरीदाबाद को मुकदमा 134/84 धारा 457/380 भाःदःसः थाना गुजेसर,जिला फरीदाबाद के मुकदमे मे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिनांक 12.02.1984 को जबकि वह थाने मे बैठा हुआ था उसने अपने भारीर पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा ली। वह सफदरजंग अस्पताल दिल्ली मे मर गया। उप निरीक्षक, नरेन्द्र सिंह, सिपाही राजैनद्र और औम प्रका ा को गैर–जिम्मेवारी के लिए निलम्बित किया गया था। उपमण्डल मैजिस्ट्रेट बल्लबगढ़ ने मृत्यू के कारण जानने के लिए जांच की थी। जांच से कोई पुलिस कर्मचारी मृत्यू के लिए जिम्मदार नही पाया गया ओर यह मामला आत्म हत्या का पाया गया था।

(3) हमीद उर्फ टूंगरी पुत्र फजरू निवासी गांव धोज, थाना सदर बल्लभगढ़ जिसको मुकदमा न. 80 दिनांक 06.08.1984 धाराधीन 302 भाःदःसः थाना सदर बल्लभगढ जिला फरीदाबाद मे पूछताछ के लिए बुलाया गया था दिनांक 11.08.1984 को अपने पेट मे दर्द होने की ि ाकायत की थी। बाद मे उनकी मृत्यु अस्पताल मे हो गई थी। उपमण्डल मैजिस्ट्रैट बल्लभगढ अभी इसकी न्यायिक जांज कर रहे हैं। इस मामले मे उप निरीक्षक नरेन्द्रसिंह को निलम्बित किया गया था। इस सम्बन्ध मे मुकादमा

न. 194 तिथी 14.08.1984 धाराधीन 304/342/323/34 भाःदःसः थाना बल्लबगढ मे सहायक उप निरिक्षक भगवानदास, प्रधान सिपाही राम निासा, सिपाही नन्द राम और औम प्रका ा और राजपाल के विरूद्व दर्ज किया गया था। यह मुकदमा अभी अनुसन्धानाधीन है।

(4) राज सिंह पुत्र भरत सिंह ब्राहमण निवासी गांव मौखरा थाना महम जिला रोहतक की मृत्यू राजकीय रेलवे थाना रेवाड़ी मे हुई थी। यह गर्मी के आकस्मिक आघात के कारण हुई थी जबकि उसे मुकदमा न 81 तिथी 02.06.1984 धाराधीन 379 भाःदःसः राजकीय रेलवे थाना रेवाडी़ मे पूछ ताछ के लिए बुलाया गया था। उप निरीक्षक निहाल सिह, सहायक उप निरिक्षक हवा सिंह और प्रधान सिपाही राम कि ान को निलम्बित किया गया था। इस मामला मे मैजिस्टरियल इन्कवायरी के आदे ा दिये गये थे ओर मैजिस्टिरियल इन्कवायरी के परिणाम प्राप्त होने पर उपरोक्त तीनें पुलिस अधिकारियों के विरूद्व विभागिय जांच की जा रही है।

(ग) दहेज के कारण महिलाऔ की मृत्यू से सम्बन्धित मुकदमे और उनकी अब तक की स्थिति का विवरण।

हां

धारा 302 भाःदःसः = 18 मुकदमें

चालान	सजा हुई	बरी हुए	न्यायालय मे विचारधीन	अनुसन्धानाधीन	खारिज
15	2	4	9	2	1

धारा 306 भाःदःसः = 38 मुकदमें

चालान	सजा हुई	बरी हुए	न्यायालय मे विचारधीन	अनुसन्धानाधीन	खारिज
33	1	10	22	2	3

दहेज से उत्पन्न झगड़ों के कारण दर्ज किए गये 56 मुकदमो का अन्य विवरण देने मे जो समया और श्रम लगेगा उसके मुकाबले कोई सम्भवव लाभ की प्राप्ति नही होगी।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, मेरें सवाल 'ग' भाग का जवाब दिया गया है–

''दहेज से उतपन्न झगड़ो के कारण दर्ज किए गये 56 मुकदमों का अन्य विवरण देने मे जो समय और श्रम लगेगा उसके मुकाबले कोई सम्भव लाभ की प्राप्ति नही होगी''

अध्यक्ष महोदय, इसमे आदमी के जीवन का सवाल है और इसको जवाब देने मे केवल चार कागजों को सवाल है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि मनुश्य का जीवन ज्यादा कीमती है या चार कागज कीमती है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, हमने बाकायदा जवाब दे रखा हैं। हमने सारी इंफरमे ानप डिटेल मे दी हुई है।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, आप देखें। इसमे लिखा हुआ है:–

''दहेज से उतपन्न झगड़ो के कारण दर्ज किए गये 56 मुकदमों का अन्य विवरण देने मे जो समय और श्रम लगेगा उसके मुकाबले कोई सम्भव लाभ की प्राप्ति नही होगी''

श्री अध्यक्षः जवाब मे जो कुछ दिया हुआ है अगर इसके अलावा कुछ ओर आपके इल्म मे है तो आप पूछिए।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, जिनकी पुलिस कस्टिडी मे मृत्यू हुई उनके बारे मे मुझे नोलिज हैं। उनमे से एक का नाम राजबी है और वह जाण्टीकंला को रहने वाला था। स्पीकर साहब, वह पुलिस कैस्टिडी मे मारा गया। उसका मुकदमा दर्ज हुआ। स्पीकर साहब, उसके घर मे दो छोटे बच्चे है और एक बूढी मां है। क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेगे कि क्या सरकार उसके बच्चों की पढाई ओर ब्याह भाादी का प्रबन्ध करेगी? दूसरा सवाल मेरा यह हे कि विवरण के अनुसार दहेज के मामले मे 56

मुकदमे दर्ज हुए है। इनमे से अठारह मुकदमे धारा 302 के अन्डर दर्ज हुए। केवल दो को सजा हुई और चार बरी हो गए। धारा 306 के तहत 38 मुकदमे दर्ज हुए इनमे से एक को सजा हुई और दस बरी हो गए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कही इन मुकदमों मे सरकार की तरफ से अनदेखी तो नही बरती गई जिससे कि ज्यादातर लोग बरी हो गए?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, इन्होने दो सवाल पूछे है और साथ यह भी कहा है कि मेरे पास जवाब ठीक नही आया। स्पीकर साहब, जवाब मे कोई कमी नही है और जवाब दिया गया है और सारा जवाब इनके पास गया भी है। जहा तक राजबीर का ताल्लूक है यह मामला अभी कोर्ट मे है। कोटग जो भी फेसला करेगी सरकार उसको मानेगी। स्पीकर साहब, जहां तक दहेज के कारण मोतों का सवाल है बहुत सी जगह औरते खुदक ाी कर लेती है या यूं कह लीजिए कि मार दी जाती है परन्तु इसके लिए गवाह चाहिए। स्पीकर साहब, आप तो काबिल वकील रहे है ओर आप जानते है कि अगर सै ान जज के सामने भी कोई कतल हो जाए ओर जब तक कोई गवाह न हो तो सै ान जज भी कुछ नही कर सकता। कुछ ऐसो मामले होते है जिनमे सबूत मिलना कठिन होता हैं। जब सबूत नही मिलता तो मुजरिम छूट जाता है। इस मामले मे सरकार की तरफ से कोई कोताही नही हुई हैं। हमारी हिदायत है कि ज्यों ही कोई रिपोर्ट दहेज के मामले मे किसी स्त्री

को जलाने के बारे मे आए या पुलिस को पता लगा, फौरन ही मुकदमा दर्ज किया जाए और फोरनव ही तफसी ा की जाए।

श्री मंगल सिंह : स्पीकर साहब, मेरे साथी श्री किताब सिंह को मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है कि महने पूरा जवाब दिया हैं। मुख्यमंत्री जी जरा पढने की कोि ा ा करे। इन्होने जवाब मे लिखा है – ''दहेज से उतपन्न झगड़ो के कारण दर्ज किए गये 56 मुकदमों का अन्य विवरण देने मे जो समय और श्रम लगेगा उसके मुकाबले कोई सम्भव लाभ की प्राप्ति नही होगी'' मै मुख्यमंत्री का ध्यान केस नम्बर 2 की और दिलाना चाहता हूं । इसमे लिखा है कि बाले पुत्र चन्दर जाति गुज्जर निवासी गांव अतमादपूर थान एन.आई.टी. फरीदाबाद को मुकदमा न. 134/83 धारा 457/380 भा.द.स. थाना गुजेसर जिला फरीदाबाद के मुकदमे मे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिनांक 12.02.1984 को जब वह थाने मे बैठा हुआ था तो उसने अपने भारीर पर मिट्टी को तेल डाल कर आग लगा ली और वह मर गया इस सम्बन्घ मे कुछ लोगो को सस्पेंउ किया गया। मैजिस्ट्रैट से इन्कवायरी कराई गई ओर जांच मे किसी पुलिस अफसर को जिम्मेवार नही पाया गया। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि पुलिस स्टे ान मे मिट्टी का तेल कहा से आया? दूसरा सवाल यह है कि क्या थाने के इन्चार्ज के खिलाफ इस बारे मे कोई ऐक ान लिया गया और अगर लिया गया तो क्या ऐक ान लिया है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस केस की तफसील ऐसी है कि बाले पुत्र चन्दर जाति गुज्जर निवासी गांव अतमादपूर थान एन.आई.टी. फरीदाबाद को मुकदमा न. 134/83 धारा 457/380 भा.द.स. थाना गुजेसर जिला फरीदाबाद के मुकदमे मे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिनांक 12.02.1984 को जबकि वह थाने मे बैठा हुआ था उसने अपने भारीर पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा ली। वह सफदरजंग अस्पताल दिल्ली मे मर गया। उप निरीक्षक, नरेन्द्र सिंह, सिपाही राजैनद्र और औम प्रका ा को गैर–जिम्मेवारी के लिए निलम्बित किया गया था। उपमण्डल मैजिस्ट्रेट बल्लबगढ़ ने मृत्यू के कारण जानने के लिए जांच की थी। जांच के कोई पुलिस कर्मचारी मृत्यू के लियसे जिम्मेदार नही पाया गया औरा यह मामाला आत्महत्या का पाया गया था।

डा. भीम सिंह दहियाः स्पीकर अगर किसी पुलिस अफसर की नेग्लीजैंनस नही थी तो उन पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को सस्पैंड क्यों किया गया? (ाोर)

श्री अध्यक्षः इसका जवाब दहिया साहब आ चुका है।

श्री मंगल सिंह : स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय केवल इनता ही बता दे कि थाने मे मिट्टी का तेल कहां से आ गया था। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, डाकटर साहब आजकल बीमारी से उठकर आये है और अपना दिमागी संतुलिन खो बैठे है। याददा त कम हो गयी है। (हंसी) मैने तफसील के साथ सब कुछ बता दिया हैं। मेहरबानी करके इनका मर्यादा मे रहकर ही बात करनी चाहियें। सुनते कम है और बोलते ज्यादा है। (ाोर एवं व्यवधान)

डा. भीम सिंह दहियाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जवाब मे चार मौतों को जिक्र किया चौथें केस मे इन्होने अपने जवाब मे बताया है कि इंटैरोगे ान के दौरान मौत हीट स्ट्रोक से हुई है। मै आपके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इंटैरोगे ान ऐसी कड़कती धूप मे करने की क्या आव यकता थी जहां कि उसकी मौत हो जाए देसरी बात यह है कि क्या हीट स्ट्रोक से ही मौत हुई थी तो फिर पुलिस अफसरों के खिलाफ एक ान लेने की क्या आव यकता थी? इस कारण से दो आदमीयों को सस्पैंड कर दिया ओर मैजिस्टरियल जांच के लियें आर्डरप भी कर दिये यह बात तो आपस मे कंट्राडिक्टरी सी हो गयी लगती है। या तो ये कहे कि हमे इसके कारण पता नही और जब इनको यह पता है कि मौत जो हुई वह हीट स्ट्रोक के कारण हुई तो जांच वगैरह की आव यकता ही नही थी। इसलिय मै इनसे साथ साथ यह भी जानना चाहता हूं कि ही स्ट्रोक से इन डैथस के सिवाये कोई और डैथस भी हरियाणा मे हुई है या नही ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस केस की कहानी इस प्रकार से है। राज सिंह पुत्र भरत सिंह ब्राहमण निवासी गांव मौखरा थाना महम जिला रोहतक की मृत्यू राजकीय रेलवे थाना रेवाड़ी मे हुई थी। यह गर्मी के आकस्मिक आघात के कारण हुई थी जबकि उसे मुकदमा न 81 तिथी 02.06.1984 धाराधीन 379 भाःदःसः राजकीय रेलवे थाना रेवाडी़ मे तफती ा के लिए बुलाया गया था। उप निरीक्षक निहाल सिह, सहायक उप निरिक्षक हवा सिंह और प्रधान सिपाही राम कि ान को निलम्बित किया गया था क्योंकि उन्होने उसको दवाई देने मे कुछ देर की थी। जब उस आदमी की तफती ा हो रही थी तो उसको उस के दौरान दवाई दिलवानी चाहिये थी। इस नैगलीजैन्स के लिए उनको सस्पैंन्ड किया गया था ताकि आगे किसी भी प्रकार को कोताही न हों।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर सर, क्या मुख्यमंत्री बतायोगे कि पुलिस स्टे ान पर जो मौतें होती है क्या वह पुलिस की ज्यादती के कारण नही होती है? क्योकि पुलिस उनका इतना पीटती है कि आदमी मर जाता है। साथ मे स्पीकर साहब, मै मुख्यमंत्री महोदय से यह भी जानना चाहती हूं कि हरियाणा मे और भी इस प्रकार के डैथस हुई है जोकि पुलिस हिररासत मे मार पीट करने से हुई हों। इन्होने तो यहां पर केवल चार का ही जिक्र किया है लेकिन और बहुत सी डैथस हुई हों। पिछले दिनो

उचाना हल्के मे ही एक डैथ हुई है। इस बात का सरकार जवाब दें।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मौत तो कही भी हो सकती हैं। बड़े बड़े महलों मे राजवाड़ो की मौत हो जाती है। राजे महराजाओं की मौत भी महल मे होती है। मौत जब आती है तो वह जगह नही देखती कि कौन सी जगह पर इन्सान की मौत होनी चाहियें। मौता का कोई समय और टाईम नही होता। इनको पता नही क्या हो गया है जो इस तरह की बाते करते है। आप स्पीकर साहब, यह जानते है कि अगर कोई चोरी के केस मे, डकैती के केस मे या 302 के केस मे किसी आदमी से क्या पुलिस बुलाकर पूछताछ करेगी? अगर पूछताछ करेगी तो उसको कुद कहना भी पड़ेगा। इसका मतलब यह नही कि मारपीट से कोई मौत होती है। पूछताछ मे तो हो नही सकता कि आओ डाक्टर, बैठो कुर्सी पर यह तो वे कह नही सकते। जिसने चौरी कर रखी हो उस से पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। पूछताछ के दरमियान या वैसे ही अगर कोई आदमी खुदक ाी कर ले तो इसमे सरकार क्या कर सकती हैं। यूंहि बिलावजह इल्जाम लगाने को कोई मतलब नही है। अगर माननीय सदस्यापें के नोटिस मे और कोई बात हो कि फलां जगह फलों व्यक्ति पुलिस की हिरासात मे मर गया तो सरकार उसका बाकायदा जवाब देगी और जैसा कि मैने पहले बताया है कि जिस अधिकारी का कसूर निकलता है, उसके खिलाफ हमने कार्यवाही की है ओर आगे भी करेगें।

श्री देवी दासः अध्यक्ष महोदय, राजबीर पुत्र करतार सिंह, निवासी जाटीकंला थाना राई, सोनीपत जिले की मौत हुई है और दो सिपाहीयों को 302 मे अरैस्ट करके, जैसाकि चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि उनके विरूद्व मामला कोर्ट मे चल रहा है मै उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन दोनो सिपाहियों का कसूर है या कि उसी थाने मे दूसरे जो हवलदार और थानेदार या एस.एच.औ. का कसूर हैं। इस बारे मे क्या चीफ मिनिस्टर साहब स्थिती का स्पश्ट करेगें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जिनका कसूर पाया गया उनका बाकायदा चालान किया हुआ है और मामला अदालत मे है। उसका अदालत ही फेसला करेगी।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री ने अपने जवाब मे यह कहा है कि राज हिस की महम थाने के जो मृत्यू हुई है वह गर्मी की वजह से हुई क्या डाक्टरी रिपोर्ट मे ऐसा लिखा है? दूसरी बात यह है कि मई, 1984 मे बिचपड़ी के बदलू उर्फ करता सिंह ने एक औरत को दहेज के कारण मार डाला है। क्या उसकी एफ.आई.आर दर्ज हुई है कि नही और इसी सम्बन्ध मे वहा पर एक बड़ी भारी पंचायत भी हुई अखबारेो मे भी यह खबर आई हे और साि मे माफी मांगते हुए फोओ भी आई है। 20–30 हजार आदमी वहा पर थे। इस लिए मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है किक इस बारे मे वह अपनी स्थिती स्पश्ट करे। स्पीकर साहब, जो आदमी पुलिस कस्टडी मे मारा गया, उसका इन्होने

बताया कि मुकदमा भी दर्ज हुआ है माने वाले के पिछे उसके बच्चे रह गये है, एक बुढी मां है लेकिन और कोई आदमी घर मे नही है। क्या उनके पालन पोशण के लिए, पढाई के लिए, भाादी वगैरह के लिए ओर सर्विस के लिए सरकार कोई प्रबन्ध करेगी?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, जहां तक इस केस का ताल्लुक है मेने बड़ा तफसील के साथ बताया है कि केस अदालत मे है ओर अदालत ही इसका फेसला करेगी कि किस का कसूर है और अदालत ही उसे सजा देगी। जहां तक इसके परिवार को सहायता देने का सम्बन्ध है इस बात को मूझे पूरा ज्ञान नही है कि उसके परिवार की क्या द ाा है। मैम्बर साहब मुण्े सारा हवाला लिखकर भेजे देवे कि उनके घर की क्या हालत है। अगर किसी बच्चे छोटे हो और चाहे उस माने वाले का कसूर भी तो तो भी सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि सरकार उसके बाल बच्चों की सहायता करें। आप लिखकर भेजिये, सरकार जो भी मदद कर सकती होगी अव य करेगी।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, 302 मे एक केस कैंसिल हुआ और 306 मे तीन केसिंल हुए, इसके क्या कारण है? दूसरी बात यह है कि इस काम के लिये कोई डी.एस.पी. रैन्क को अफसर अप्वांयट करेगे जो कि इसकी जांच करें या किसी स्पै ाल ऐजेन्सी को यह काम सौंपा जाएगा क्योकि छोटे अफसर पैसे लेकर लोगो के साथ मिलजाते है और केस की तफती ा

अच्छी तरह से नही हो पाती हैं। क्या इस तरह के केसिज के लिए कोई स्पै ाल कोर्ट भी सरकार बनाने का विचार रखती हैं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, एक आदमी को जेठप के महीने मे कही पकड़ लिया और अन्दर कर दिया और सावन के महीने के बाहर आया तो उसे सूखा ही सूखा दिखायी देने लगा। इसका भी यही हाल है कि इनको तो हर तरफ पैसे के सिवा कुछ नजर नही आता है। (ाोर)

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मैने जो कहा है यह बिल्कूल ठीक है ये जांच करवा लें।

चौधरी भजन लालः माननीय स्दस्यों को स्पीकर साहब, जिम्मेवारी के साथ सारी बाते कहनी चाहिये। एज ए होल सब के लिए ऐसा नही करना चाहिए कि नीचे के सारे के सारे अफसर बेईमान है। मै यह तो कह सकता हूं कि कमियां तो हम सब मे हो सकती है, सरकारी अधिकारियों मे भी हो सकती है। यहां ऐज ए होल सभी को कह देना यह कोई अच्छी बात नही हैं। अध्यक्ष महोदय, बाकायदा डी.एस.पी. रैन्क का आदमी इन्कवायरी करता है, देखता है और जिसका कसूर होता है, उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करती है। (ाोर एंव व्यवधान)

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, बिचपड़ी मे जो पंचायत हुई थी उसका क्या हुआ। कोई केस दर्ज हुआ कि नही। जरा इस बारे मे तो बता दें। (ाोर) और साथ ही मैडीकल

रिपोर्ट क्या थी उसका भी जरा हमे पता लगना चाहियें। इन्होने यह कैसे कह दिया कि आदमी गर्मी के कारण मर गया। आया इनके पास कोई मैडीकल रिपोर्ट आई है?

श्री अध्यक्षः चौधरी किताब सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर साहब यह ब्यान देते है कि आदमी हीट स्ट्रोक से मरा तो किसी मैडीकल रिपोर्ट के आधार पर ही कहते होगें।

साहेगार अब सवालों का समय खत्म होतो है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर

Chamarian Brahamanwas Minor

***837. Sh. Hari Chand Hooda:** Will the Minister for Irrigation and Power b pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Chamarian Brahamanwas Minor in Rohtak District; if so, the time by which the construction work thereon is likely to be started?

सिचांई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): जी हां। कार्य ीघ्र ही आरम्भ हो जाने की सम्भावना है।

S.Y.L. CANAL

***876. Sh. Hira Nand Arya & Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased

to state the steps, if any, taken by the State Government since 01-09-1984 to ensure expeditious completion of S.Y.L. Canal in Punjab Territory together with the extent up to which the said Canal has been completed?

सिचांई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): पंजाब क्षेत्र मे एस.वाई.एल. प्रौजैक्ट के कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए समय–2 पर बैठकों का आयोजन किया गया था। अन्तिम दो बैठके सदस्य (पी. एण्ड. पी.) कैन्द्रीय जल आयेग नई दिल्ली का प्रधानता मे दिनांक 30.10.1984 और 12.02.1985 को हुंई हैं। इन बैठको मे भूमि अभिग्रहण, खुदाई, लाईनिंग, बडे तक्था मध्यम क्रास ड्रैनेज कार्यो सम्बन्धी टैण्डरज को अन्तिम रूप देने बारे कार्यो का जायदा लिया गया ताकि कार्यो की प्रगति को तेज किया जा सके। इसके अतिरिक्त 01.09.1984 से पंजाब को 15 करोड़ रूपये की रा ि। इन कार्यो को execute करने हेतू दी जा चुकी है।

एक विवरणी जिसमे इस समय तक हुई प्रगति का ब्यौरा है, सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

(क) भूमि अर्जन

2351.14 एकड़ भूमि मे स 2091.41 एकड़ भूमि रीच 0. 32 कि.मी. तथा 66–112 कि.मी. मे अर्जित कर ली गई है और लगभग 6 करोड़ की अदायगी कर दी गई है रीच 32–38 कि.मी.

के लिये भूमि अर्जन हेतू अधिसूचना जारी कर दी गई है। भोश लम्बाई के लिये, अधिसूचना सम्बन्धी दस्तावेज तैयार किये जा रहे है।

(ख) मिट्टी का काम

लगभग 50 किलोमीटर के क्षेत्र मे खुदाई का कार्य भाुरू कर दिया गया है और अनुमानित 450 लाख क्यूसिक क्षेत्र मे से 90 लाख क्यूसिंक क्षेत्र मे मिट्टी का का 15.01.1985 तक पूरा कर दिया गया है।

(ग) जलमार्गो को पक्का करना

लगभग एक दर्जन स्ीानों पर लगभग 11.5 किलोमीटर लम्बाई पक्का करने के लिए पड़ी है। यह अभी आरम्भ किया जाना है।

(घ) मुख्य क्रास जलनिकास निमार्ण कार्य

सिरसा तथा वुधकी का डिजाई अनुमोदित हो गया है। सिरकसा नाला पर कार्य भाुरू कर दिया गया है। 9 अन्य मुख्य निमार्ण कार्यो की निविदाओं को अन्तिक रूप दिया जा रहा है।

(ड़) मध्यम क्रास जल निकास निमार्ण कार्य

अल्लावास, खरोआ, पारीवार, बिछोड़ा तथा मजरी क्रास जल निकास निमार्ण कार्यो की नीवों की खुदाई का कार्य भाुरू कर

दिया गया है। कई अन्य निर्माणों के कार्य भी निमार्ण कार्य एजेंसियों को अलाट कर दिये गये है।

Staff for upgraded School in village Gochhi

***881. Smt. Basanti Devi:** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether the required staff has been posted in the school of Gochhi village after its upgradation from primary to Middle, if not, the time by which the required staff is likely to be posted?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): ग्राम गोच्छी जिला रोहतक के प्राईमरी स्कूल का दर्जा बढा कर मिडल नही किया गया हैं। इसलिए इस बिना पर स्टाफ लगाने का प्र न ही नही उठता।

Electricity Generated by Panipat and Faridabad Thermal Plants

***909. Sh. Mangal Sein:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is fact that the Panipat and Faridabad Thermal Plants have been generating Electricitiy lesser than their instlled Capacity during the period from 01-01-1985 to date; if so, the Quantum of Electricitiy produced together with the reasons for generating lesser Electricitiy than the installed capacity thereof?

सिचांई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): वांछित सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरणी

दिनांक 01.01.1986 से पानीपत एंव फरीदाबाद थर्मल परियोजनाओं की बिजली उत्पादन निम्न प्रकार थी–

पानीपत थर्मल परियोजना			पानीपत थर्मल परियोजना	
	लक्ष्य	बिजली उत्पादन	लक्ष्य	बिजली उत्पादन
जनवरी, 1985	90 मै.वा.	86 मै.वा.	46 मै.वा.	43 मै.वा.
फरवरी, 1985	90 मै.वा.	94 मै.वा.	56 मै.वा.	41 मै.वा.

जनवरी तथा फरवरी, 1985 मास के दौरना पानीपत थर्मल परियोजना मे बिजली उत्पादन एंव जनवरी 1985 मास के लिए फरीदाबाद थर्मल प्लांट परियोजना मे बिजली उत्पादन लक्ष्यो के बराबर की थी। यदपि थर्मल परियोजना मे फरवरी 1985 मास के लिए बिजली उत्पादन 60 मैगावपाट की पहली यूनिट के कैपिटल मैनटैनैन्स (बड़ी अनुरक्षण) एंव जांच परीक्षण तथा चालू होने के अधीन रहने के कारण कम था।

पानीपत थर्मल स्टे ान के लिए जनवरी तथा फरवरी 1985 के दौरान लोड फैक्टर क्रम ा: स्टे ान के लिए जनवरी तथा फरवरी 1985 के दौरान लोड फैक्टर क्रम ा: 52 प्रति ात तथा 63.5 प्रति ात रहा है जो कि सामान्य कार्यकु ालता से बिल्कूल अधिक है।

Construction Roads of 'A' Class Municipal Committees

***919. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister for Local Government be pleased to state whether there is any porposal under Consideration of the Government to get the roads of "A" Class Municipal Committees in the State Constucted through the P.W.D. (B&R) if so, the time by which the said proposal is likely to materialise?

सीानीय भाासन राज्य मंत्री (श्री प्यारा सिंह): नही।

Adhoc Teachers

***886. Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the Minister of state for education be pleased to state—

(a) The category-wise number of adhoc teachers working in the Government School, in the State as on 30th Dec. 1984; and

(b) the details of the policy with regard to the recruitment and absorption of teachers referred to in part (a) above?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) दिनांक 30.12.1984 की स्थिती अनुसार तदर्थ अध्यापकों की वर्श वार संख्या निम्न प्रकार हैः

1.	स्कूल प्राध्यापक	12
2.	मास्टर / मिस्ट्रेसिज	2379
3.	जे.बी.टी.	3856
4.	हिन्दी अध्यापक	929
5.	संस्कृत अध्यापक	579
6.	पंजाबी	149
7.	उर्दू	84
8.	पी.टी.आई.	509
9.	ड्राईंग	417
10.	सिलाई अध्यापिका	11
योग		8925

(ख) तदर्थ नियूक्तियां केवल उपल्ब्ध रिक्तियों के विरूद्व स्ओप गैप अरैंजमैंट के तौर पर नियमित नियूक्तियां होने तक की जाती हैं। इसलिए तदर्थ आधार पर नियूक्त व्यक्ति की सेवाए ज्यूं

ही नियमित रूप मे नियूक्त व्यक्ति कार्य ग्रहण करता हैं, समाप्त कर दी जाती है। इसलिए ऐसे तदर्थ आधार पर नियूक्त व्यक्ति को समायोजित करने की कोई नीति नही है?

Provision of Double Link Roads

***936. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state wether the facility of double link roads has been provided in any of the villages in the state; if so, the constituency-wise names of such villges.

अन्तरिम उत्तर

डी.औ. न. 29–15–85 भः तथा सः (3)

अमर सिंह

लोक निर्माण(भवन व सड़के) मंत्री

हरियाणा सरकार

चण्डीगढ।

दिनांक मार्च 15, 1985

विशयः तारांकित विधान सभा प्र न न. 936

प्रिय श्री

विधान सभा तारांकित प्र न न. 936 जो 20.03.1985 की सूची मे श्री फतेह चन्द विज, सदस्य, हरियाणा विधान सभा के

नाम दर्ज है के विशय मे मुझे यह कहना है कि उक्त प्र न का उत्तर अभी तैयार नही हुआ है क्योंकि सूचना अधीनस्थ कार्यालायों एकत्रित की जानी है। इसलिए इसमे समय लगेगा। अनुरोध है कि इस प्र न का उत्तर देने के लिए 2 मास का समय दिया जायें।

आपका

हस्ताक्षर

(अमर सिंह)

श्री तारा सिंह

अध्यक्ष

हरियाणा विधान सभा

चण्डीगढ

Forest Department Nusery in District Sirsa.

***944. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister for Forests and Jails be pleased to state—

(a) Whether any nusery was planted by the Forest Department on private land in village Darbakalan of District Sirsa; and

(b) if so, whether any compensation has been paid to any of the owners of the said land?

वन तथा जेल मंत्री (श्री गोवर्धन दास चौहान):

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

श्री अध्यक्षः अब फाईनैंस मिनिस्टर साहब वर्श 1985–86 का बजट प्रैजेंट करेगें

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, रोहतक मे पिछले 6 दिनों से पीने का पानी नही मिल रहा है। म्यूनिसिपल टैप्स मे गन्दा पानी आ रहा है। जो हरूमेन कंजम्प ान के लिए हानिकारक है। मुख्यमंत्री जी इस बारे मे जरा बता दें।

श्री अध्यक्षः डा. साहब मै आपको एक बात बताना चाहता हू कि जिस दिन बजट प्रैजैंट होना हो, उस दिन कोई और आईटम बीच मे नही आया करती।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इस मे क्या हर्ज है।

श्री अध्यक्षः प्रेसीडैंट यही है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, कोई अच्छा प्रेसीडैंट डालने मे क्या हर्ज है।(ाोर)

मुख्यमंत्री (श्री भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन की बात का कोई मतलब नही है। डा. साहब कल मेरे पास आए थे और इनहोने जिक्र किया था कि वहा पीने के पानी की दिक्कत है। मैने इनके सामने डिप्टी कमि ानर रोहतक के साथ बात की

थी। नहर का पानी बन्द होने की वहज से भाहर मे पानी नही आ सका। आज पानी पहूंच जाएगा क्योकि नहर मे पानी चल पड़ा है। (ाोर)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, जिन लोगो ने इस मामल मे कोताही की है क्या उनके खिलाफ एक ान लिया जाएगा? (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैने चौधरी औम प्रका ा के इसी विशय पर काल अटेन्ा ान मो ान पर गवर्नमैंट के कमैंट्स मांगे है। उसके साथ इस को भी लिंक कर दिया जाएगा। एप्रोप्रिएट टाईम पर आप को भी स्पलीमैंटरी पूछने का पूरा हक होगा।

वर्श 1985–86 का बजट पे ा करना

श्री अध्यक्षः अब फाईनैंस मिनिस्टर वर्श 1985–86 का बजट प्रैजैंट करेगे।

वित्तमंत्री (श्री सागर राम गुप्ता): श्रीमान अध्यक्ष महोदय, तथा मेरे मान्य साथियों,

इस गरीमा ाली सदन के सामने राज्य सरकार के वर्श 1985–86 मे बजट अनुमान और समाप्त होने वाले वर्श को संक्षिप्त विवरण पे ा करते हुए मै अत्यन्त गौरव का अनुभव कर रहा हूं।

वर्श 1984–85 भारतीय इतिहास के एक घटनापूर्ण युग के अन्त और राश्ट्र के जीवन मे एक नये युग के आरम्भ को

अंकित करता हैं। 31 अक्तुबर 1984 को हमारी महान नेता और प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नृ ांस हत्यारों की गोलियों से आहत होकर अपने जीवनकी अन्तिम सांस ली। उस महान महिला और महान नेता के लिये प्र ांसा और स्तुति के कोई भी भाब्द कभी काफी नही रहेगें।

वह न केवल राश्ट्रमंच पर एक दैवी व्यक्तित्व के रूप मे उभरी अपितु आधुनिक युग के वि व–नेताओं मे उनका प्रमुख स्ाान रहा। भाान्ति, प्रगति और समृद्वि तो जैसे उनके नाम मे पर्यायवाची भाब्द बन गए थें। उनकी मृत्यू के साथ एक महान युग का अन्त हो गया है।

हमारे सौभाग्य से और राश्ट्र के सौभाग्य से इस भाौकपूर्ण स्थिती मे भी हमारी महान जनता को आत्मबल नही डगमगाया ओर उसने समय की आव यकता को समझते हुए हमारे युवा नेता तथा नये प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को भारी जनादे ा दिया। श्री राजीव गांधी के आगमन से नई आ ाओं, नई उमंगों और राश्ट्र की सम्सयाओं के समाधान के लिए दृढ वि वास के एक नए युग का सुत्रपात हुआ हैं। यह सचमुच एक उचित और भाुभ संयोग है कि छठी पंचवर्शीय योजना की समाप्ति और सातवी योजना अवधि का आरम्भ उनके नेतृत्व मे हो रहा है।

केन्द्रिय बजट की मुख्य बातें

1985–86 का केन्द्रिय बजट कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया गया है। यह एक वृद्वि परक बजट है और नई सरकार को सामाजिक समानता के अनुरूप विकास की गति को तेज करने की इच्छा को पर्णतः वयक्त करता है। समाज के सभी वर्गो द्वारा बजट का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है।एक प्रमुख राश्ट्रीय समाचार पत्र ने नए बजट की प्र ांसा निम्न भाब्दो मे की है।

''नई सरकार ने अपना वचन पूरा किया है उत्पादन ील आधुनिक अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत बेहतर सामातिक न्याय के युग को लाने के लिये एक साहसिक कदम उठाया गया है।''

यह बजट केन्द्रिय सरकार की बेहतर वितीय अनु ाासन तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के प्रति उत्सुकता को प्रकट करता है। हम केन्द्रिय बजट का पूर्णतः स्वागत करते है। प्रधान मंत्री तथा कैन्द्रिय वित्त मंत्री को नई पद्धिती तथा वृद्धि परक उपाय अपनाने के लिये बधाई देते है। अपने सीमित साधनों और गति कौ ाल की सीमाओं मे रहते हुए हम केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गति का अनुसरण करेगें।

मै केन्द्रीय बजट की कुद प्रमुख बातों को संक्षेप मे पुनः वर्ण करना चाहूंगा।

केन्द्रीय बजट मे राजे की योजनाओ के लिए केन्द्रीय सहायता के उच्चतर उपबन्ध और राज्यों के बाजार–ऋण मे भी

उच्चतर हिस्से की व्यवस्था है। प्रत्येक राज्य मे संसाधनों के वास्तविक प्रवाह का विस्तृत विवरण तो कुछ देर बात ज्ञात होंगो। तथापि मुझे वि वास है कि 1985–86 के दौरान इन भीर्शो के अधी हम कुछ और अधिक प्राप्त करने की आ ाा करते है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने प्र ाासन आधुनिकीकरण पर और प्र ाासन मे तकनीकी सहायताओं के उपयोग के प्रारम्भ पर भारी बल दिया है। नई सरकार का प्रगति ाील दृश्टिकोण उसके द्वारा कारधान और लाईसैंस देने संबंधी नीतियों को उदार बनाने के निर्णय और कम्पूयूटरों इत्यादि पर सीमा ाुल्क मे रियायत देने से भी स्पश्ट होता हे। हम आ ाा करते है कि इन स्थितीयों से हमारा राज्य भी लाभन्वित होगा और ये उपाय हरियाणा मे इलैक्ट्रनिक्स तथा अन्य उधोगो को स्ाापित करने के राज्य सरकार के प्रयत्नों को बढावा देगें।

केन्द्रीय बजट बेहतर सामाजिक सुरक्षा तथा व्यापक फसल–बीमा लागूं करने की केन्द्रीय सरकार की इच्छा को परिलक्षित करता है। मुझे वि वास है कि नई नीति से हरियाणा सहित समूचे दे ा को खेतिहार समुदाय लाभाविन्त होगा।

हमारे लिये भी यह समय लेखे जोखे का है वि ोशत– इसलिये कि कुछ ही दिनों मे छठी पंचवर्शीय योजना की अवधि समाप्त हो रही है और अगले महीने की पहली तारीख से सातवी योजना भाुरू हो रही है।

आर्थिक सर्वेक्षण

हरियाणा का अर्थिक सर्वेक्षण 1984–85 दस्तावेज जिसमे राज्यवा की आर्थिक स्थिति का विस्तृत वि लेशण और आर्थिक मोर्चे पर राज्य सरकार की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है, की प्रतियों माननीय सदस्यों के पास पहले से ही उपलब्ध है तथापि, हमारी आर्थिकता के महत्वपर्ण पहलुओ और उल्लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र मै संक्षेप मे करना चाहूंगा।

कुछ अवधिओ मे खराब मौसम और कुछ ऐसी अन्य विपरीत स्थितियों के होत हुए भी जो कि हमारे काबू से बाहर थी, छठी योजना के दौरान राज्य की अर्थिकता मे निरन्तर वृद्वि होती रही है। छठी योजना के आरम्भ होने से ठीक पहले वाले वर्श मे अर्थात 1979–80 मे राज्य का घरेलू उत्पादन स्थिर मूंलयो (1970–71) पर 1200 करोड़ रूपये था जो 1983–84 मे 1547 करोड़ रूपयों तक बढ गया ओर नवीनतम अनुमानों के अनुसरार 1984–85 मे इसके 1592 करोड़ रूपयों तक पहुंचने को अन्दाजा है। इसी तरह वर्तमान मूल्यो पर राज्य की आय, जो कि 1979–80 मे 2423 करोड़ रूपये थी, 1983–84 मे 4320 करोड़ रूपये तक पहुंच गई थी। क्षेत्रवार वि लेशण से पता चलता है कि प्रारंभिक क्षेत्र मे स्थिर मूल्यो पर राज्य का उत्पादन 1979–80 मे 581.2 करोड़ रूपयों से बढकरप 1983–84 मे 762.4 करोड रूपयो पर पहुंच गया, द्वितीय क्षेत्र मे 1979–80 मे 254.6 करेाड रूपयों से बढकर 1983–84 मे 305.6 करेाड रूपयों तक और तृतीय क्षेत्र मे

1979–80 मे 364.2 करेाड रूपयों से बढकर 1983–84 मे 479 करेाड रूपयों तक बए गया। समूचे तौर पर प्रारम्भिक क्षेत्र का 1970–71 मे 64.8 प्रति ात का अ ादान घटकर 1983–84 मे 46.1 प्रति ात रह गया। द्वितीय क्षेत्र का अं ादान 15.2 प्रति ात से बढकर 23.6 प्रति ात हो गया और तृतीय क्षेत्र का अं ादान इसी अवधि मे 20 प्रति ात से बढकर 30.3 प्रति ात हो गया। ये रूझान सुखद कहे जा सकते हैं।

हमारा राज्य प्रतिवयक्ति आय मे भी उन्नति की ओर अग्रसर रहा है। वर्तमान मूल्यो पर हमारी प्रतिव्यक्ति आय 1979–80 मे 1949 रूपए से बढ़ कर 1983–84 मे 3147 रूपए हो गई और इस प्रकार केवल 4 वर्श मे 61 प्रति ात अधिक वृद्वि हुई।

छठी पंच वर्शीय योजना (1980–85) 1800 करोड़ रूपए अनुमोदित परिव्यय के आधार पर बनाई गई थी जिसके मुकाबिले मे हमारे द्वारा लगभग 1638 करोड़ रूपए का खर्च किए जाने की संभावना है जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण योजना स्कीमों पर खर्च किए गए लगभग 35 करोड़ रूपए भी सम्मिलित है। वस्तुतः यदि कुद अप्रत्याि ात देयताए न होती, जैसे कि कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मंहगाई भते की कि तो की स्वीकृत, कुछ निर्धारित मूल्यों मे वृद्वि और राहत उपायो पर खर्च की गई रा ि। जो कि इन पांच वर्शो मे लगभग 570 करोड़ रूपए के

लगभग रही तो हमारो योजना व्यय 1800 करोड़ रूपए के मूल पव्यिय से बहुत अधिक हो जाता।

यधपि दे ा मे वर्तमान कीमतो के रूझान से राज्य पूर्णतः अप्रभावित तो नही रहा सकता तथापि हम इन दबावों के यथासंभव सीमा तक रोकने के लिए प्रयत्न ील रहे है। हरियणा राज्य कामगार–श्रेणी–उपभोक्ता–मुल्य–सुचकांक मे मार्च 1983 और मार्च 1984 के बीच केवल 6.5 प्रति ात की वृद्वि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय कामगार–श्रेणी–उपभोक्ता–मुल्य–सुचकांक मे 11.2 प्रति ात की वृद्वि हुई। इसी प्रकार कृशि–साम्रगी के थोक मूल्यों के सूचकांक मे दिसम्बर 1983 और दिसम्बर 1984 के बीच केवल 4 प्रति ात की वृद्वि पिछलें वर्श की इसी अवधि के दोरान 9.2 प्रति ात की वृद्वि के मुकाबिले मे हुई। राज्य सरकार ने अपनी 6000 उचित मुल्य दुकानों के व्यापक जाल के द्वारा राज्य के लोगो को उचित मूल्यों पर आव यक वस्तुओ की आपूर्ति प्रर्याप्त मात्रा मे विनियमित एंव सुनि ि चत करने के लिए प्रयास किए है। इनमे से 241 उचित मूल्य दुकाने केवल समाज के कमजोंर वर्गो के लाभ के लिए चलाई जा रही है।

पूजी निर्माण

सरकार सार्वजनिक तथा निजी दोना ही क्षेत्रों मे उच्चतर पूंजी निर्माण के लिए प्रयतन ील रही हैं। बजट अनुमान

1984–85 का आर्थिक और कार्यात्क वर्गीकरण प्रकट करता है कि राज्य सरकार की 459.6 करोड़ रूपए की कुल प्रत्यक्ष मांग मे से 147.9 करोड़ रूपए की रा ि ा अथवा 32.2 प्रति ात का उपबन्ध इसके अपने पूंजी निर्माण क लिए किया गया है और 135 करोड़ रूपए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के पूजी निर्माण मे राज्य का अं ादान है। इस प्रकार अकेले 1984–85 के दौनान कुल लगभग 283 करोड़ रूपए का पूंजी निर्माण होगा जो कि पिछले वर्श की अपेक्षा लगभग 5.6 प्रति ात अधिक है। कुल निवल बचतों का अनुमान लगभग 159 करोड़ रूपए लगाया गया है। ये आकड़े पर्याप्त रूप से संकेत देते है कि राज्य सरकार बढ़े हुए स्तर के निवे ा का उपबन्ध करने और उसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

सं ाोधित योजना परिव्यय 1984–85

मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारी विव ाताओ के बावजूद 1984–85 का सं ाोधित योजना परिव्यय बजट परिव्यय से बढा हुआ हैं। 429.3 करोड़ रूपए के मूल अनुमानों के मुकाबिले मे हमने 433.3 करोड़ रूपए के सं ाोधित परिव्यय का उपबन्ध किया है। यह राज्या सरकार की एक महत्वपर्ण उपलब्धि है जो हमारे योजनेतर व्यय मे कठोर वित–अनु ाासन तथा भारत सरकार के द्वारा दिखाई गई उदार वृति के कारण संभव हो सकी है।

पांच वर्शो की अवधि के दौरान योजना व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा सिंचाई और बिजली तथा उसके बाद सामाजिक और सामुदायिक सेवाओ और कृशि को गया है। सिंचाई तथा बिजली क्षेत्र को लगभग 966 करोड़ रूपए (योजना व्यय का लगभग 59 प्रति ात) के आबटन से राज्या सिंचाई अधीन क्षेत्र को 3.52 लाख हैक्टैयर और बढा सकने मे समर्थ हुआ, नलकूपो की संख्या लगभग एक लाख बढ गई है और बिजली–उत्पादन–क्षमता लगभग 362 मैगावाट बढ गई हैं।

सामाजिक तथा समुदायिक सेवाओ मे ज्यादा हिस्सा ि ाक्षा, स्वास्थय, चिकित्सा–सुविधाओ तथा पेयजल आपूर्ति और मल–निकास–योजना को गया हैं। कृशि–विकासा पर परिव्यय से अधिक उत्पादन से अधिक उत्पादन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप राज्य सम्भवतः चालू कृशि वर्श के दौरान 71 लाख टन का रिकार्ड खाधान्न–उत्पादन हासिल कर सकेगा। गत पांच वर्शो मे खधान्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन क्षेत्र लगभग 6 लाख हैक्टेयर बढा दिया गया है और उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों की खपत 60 प्रति ात से भी अधिक बढ़ गई हैं।

इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणीयों और समाज के अर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के क्लयाण पर वि ोश ध्यान दिया गया है। इन पर लगभगप 16.5 करोड़ रूपये का योजना खर्च किया गया हैं।

सातवी पंचवर्शीय योजना

राज्य सरकार ने सातवी पंचवर्शीय योजना के लिए वृद्वि समानता तथा सामाजिक न्याय, आत्म निर्भरता, उन्नत कु ालता तथा उत्पादकता के व्यापक उदे यों को ध्यान मे रखते हुए 3200 करोड रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव अनन्तिक रूप मे रखा है। इन मूलभूत मार्गद र्ी सिद्वातों के अन्तर्गत सातवी योजना के महत्वपर्ण अंग निम्नानुसार है:–

(i) आयाजना का विकेन्द्रीयकरण तथा विकास मे लोगो की पूर्ण सहभागिता:

(ii) उत्पादक रोजगार का अधिकतम सम्भव उत्पादन:

(iii) गरीबी मे कमी करना तथा अन्तर्वर्गीय, अन्तर्क्षेत्रीय तथा ग्रामीण– ाहरी असमानताओं मे कमी करना:

(iv) सामाजिक खपत वि ोशतया ि ाक्षा, स्वास्थय, पोशण, सफाईपप तथा आवास का उच्चतर स्तर:

(v) छोटे परिवार के नार्म को स्वैच्छिक रूप से अपनाने को तेज करना तथा आर्थिक एव सामाजिक कार्यो मे महिलाओ के लिए सकारत्मक भूमिका:

(vi) समूची अर्थ व्यवस्था मे आधारित सरंचनाओ की रूकावटो ओर कमियों को कम करना तथा उन्नत क्षमता–उपयोगिता तथा उत्पादकता:

(vii) उधोग मे कुल ाता, आधुनिकीरण तथा प्रतियोगिताः

(viii) ऊर्जा का संरक्षण तथा गैर पारमपरिक ऊर्जा स्त्रोतो को बढावाः तथा

(ix) विकास– आयेजना की मुख्य धारा मे विज्ञान तथा प्रोधोगिकी का समेकन, तथा परिस्थितिक एंव पर्यावरणीय संरक्षण।

राज्य सरकार उन प्राथमिकताओं को पूरी तरह पालन करती है तो सातवी योजना के लिए एप्रोच–पेपर तैयार करते समय केन्द्र सरकार द्वारा निधार्रित की गई है। हम हरियाणा के लोगो की जीवन स्थितियों मे गुणत्मक सुधार लाने तथा अधिक वृद्वि, सामाजिक न्याय, अधिक कु ालता तथा बेहतर सुअवसर जुटाने के लिए पुर्णतः वचनबद्व है। सातवी पंचवर्शीय योजना –अवधि के लिए हमारे परियोजित आबटन हन मूल दि ाा निर्दे ाों से ही उभरते है, आर्थिक नीति की मुख्य वि ोताए होगी, बेहतर सिंचाई–सुविधाओं और बिजली की उपलब्धता द्वारा कृशि–विकासा, कृशि, उधोग तथा अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक बिजली–उत्पादन, किसानों के लिए अच्छी किस्म के निविश्टों की व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण, उधोग की वृद्वि, मानव–संसाधनो मे अधिक निवे ा, ि ाक्षा, चिकित्सा तथा स्वास्थय–सम्बन्धी अच्छी सुविधाओ की व्यवस्था, व्यवसायिक

प्रि ाक्षण, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों का उत्थान और आवास, पेयजल आपूर्ति जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करना।

सतलुज–यमुना–सपर्क–नहर–परियोजना

राज्या सरकार के मुख्य प्रयासों मे से एक प्रयास है हमारे किसानों को सिचाई–सुविधाए प्रदान करने केल लिए सतलुज–यमुना–सपर्क–नहर–परियोजना का निमार्ण करना। हाल मे परियोजना पर कार्य तेजी से चलने लगा हैं और परियोजना के निश्पादन की गति सर्वथा उत्साह–जनक हो गई हें इसके लिए पंजाब सरकार तथा सतलुज–यमुना–सपर्क–नहर–परियोजना प्राधिकारी हमारी बधाई के पात्र है। भारत सरकार इस परियोजना की प्रगति का परिवीक्षण बहुत बारीकी से करने के लिए कृपापूर्वक सहमत हो गई है। निःसदेह इस सम्बन्ध मे हम उनके अभारी है कि वह इस परियोजना मे इतनी अधिक रूचि ले रहे है। मै इस परियोजना के एक महत्वपुर्ण पहलू पर सदन को वि वास मे लेना चाहता हूं। चूकि परियोजना राश्ट्रीय महत्व की है जिस पर कि बहुत अधिक परिव्यय होगा, अतः हम ने इस परियोजना के लिए अग्रिम सहायता देने हेतू भारत सरकार से वि ोश अनुरोध किया है। फिलहाल हमारी प्राथ्रना को स्वीकार्य समझेगी। मै समझता हू कि तकनिकी तौर पर इस परियोजना को अगामी दो वर्शो मे पूरा किया जा सकता है। मूझे वि वास है, भारत सरकार के अनुग्रह और उस द्वारा ली गई सक्रिय रूचि से तथा हाल ही मे पंजाब

सरकार तथा परियोजना–प्रधिकारियों द्वारा रूचि लेने से सम्भव है कि हम इसे लक्ष्य–तिथी से भी पहले पूरा कर लें।

हरियाणा सिंचाई परियोजना चरण II वि व बैंक की सहायता से अप्रैल, 1983 मे भुरू किया गया था जिस मे नहरों के 25 करोड़ वर्ग फुट को पक्का काने की मन ा थी। इस परियोजना के मार्च 1988 तक पूरा होने की सम्भावना हैं। 31 मार्च 1984 तक नहरों के लगभग 8.6 करोड़ वर्गफुट को पक्का करने का काम पूरा हो गया है। वर्श 1985–86 के दोरान इस परियोजना के लिए 26 करोड़ रूपए का परिव्यय है।

वर्श 1983–84 मे हरियाणा मे फिरप से बाढों ने तबाही मचा दी थी। बाढ नियंत्रण तथा जल–निकास के लिए एक मुख्य योजना पहले ही निश्पादित की जा रही है। अक तक राज्या मे 18 लाख हैक्टेयर के बाढ–सम्भावी क्षेत्र मे से 15 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बाढों से सुरिक्षित कर दिया गया हैं। वर्श 1985–86 के दौरन बाढ़ नियंत्रण तथा जल–निकास स्कीमो के लिए 14 करोड़ रूपए की रा ि ा के लिए उपबन्ध किए जाने का प्रस्ताव है।

बिजली

बिजली आधुनिक समाज का जीवनधार है और किसी भी सार्थक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित मूलभूत ढांचे का काम देती हैं। राज्य सरकार इस क्षेत्र मे निधियो के अधिक निवे ा तथा कु ाल प्रबन्ध व्यवस्था–इन दोनो को ही सर्वोच्च प्राथमिकता

देती है। किए गए प्रयासों के फलस्वरूप ताप–यूनिटोमे बिजली उत्पादन मे पहले ही उत्पादन मे पहले ही उल्लेखनीय सुधार हुआ हैं। पारपेशण और वितरण–प्रणाली को सुप्रवाही बनाया जा रहा है और निर्माणधीन परियोजनाओं के समय पर चालू होने के परिवीक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे है। वर्श 1985–86 मे बिजली के क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रूपए के परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है पानीपत ताप विधुत संयन्त्र यूनिट 3 तथा 4 को आगामी वर्श के दौरान चालू किए जाने की सम्भावना है। जिस से हमारी ताप विधुत क्षमता 220 मैगावाट बढ जायेगी। इसके अतिरिक्त पि चम यमुना नहर परियोजना के 8 मैगावाट प्रत्येक वाले दो यूनिटो को आगामी वर्श मे चालू करने को लक्ष्य है। यमुनानगर ताप विधुत परियोजना पर कार्य गति के आगामी वर्श मे तेज हो जाने की सम्भावना है। ताप तथा पन–बिजली–स्त्रोतों का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त, राज्य सरकार, हरियणा मे एक परमाणू–बिजली–संयन्त्र की सीापना करने के लिए भी भारत सरकार से एक प्रस्ताव की पैरवी कर रही है।

कृशि

हमारे योजनाबद्व विकास मे कृशि का सीान अब भी प्राथमिक्ता क्षेत्र का है। चालू वर्श के दौरान 71 लाख टन की संभावित उपलब्धि के मुकाबले मे खाधान्नो आगामी वर्श के लिए के लिए गन्ने का लक्ष्य 7.65 लाख अन और कपास का लक्ष्य 8 लाख गाठें नियत किया जा रहा है। वर्श 1985–86 के लिए कृशि

तथा वनो पर योजना परिव्यय के 28 करोड़ रूपए से अधिक हो जाने की संभावनां है। अगामी वित्त वर्श के दोरान, 2500 बायोगेस संयन्त्रो के लगाया जाने का प्रस्ताव है। लगभग 12 करोड़ रूपये के परिव्यय की व्यवस्था समेकित ग्रामीण विकास कार्य{म के लिए की जा रही हैं इससे गरीब की रेखा से नीचे वाले 85700 परिवरो को सहायता प्रापत हो मरूभूमि तथा सूखा–संभावी–क्षेत्र–विकास कार्य{म के लिए 4.89 करोड़ रूपये के उपल्ब्ध का प्रस्ताव है। मेवाल क्षेत्र के सधन तथा चौमुखी विकास के लिए 2.5 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव है।

प ुपालन तथा मछली पालन

खेतिहर समुदाय की आय का बढाने तथा कमजोर वर्गों की स्थिती सुधारने के दृश्टिगत प ुपालन मछली पालन तथा डैरी विकास परियोजनाओं पर दिया जा रहा हैं वर्श 1985–86 के दोरान 40 नए प ु चिकित्सा आशधालयों एक पालिक्लिक खोले जाने का प्रस्ताव है। 30 प ु चिकित्सा औशधालयों हस्पतालों मे बदलने का प्रस्ताव है। गरीब ग्रामवासियों को मछली पालन मे सहायता देने के लिए छः मछली–पालक–विकास–एजेंसिया सीापित कर दी गई मछली उत्पादन के 10000 टन के वर्तमान स्तर के सातवी योजना अवधि के अंत तक दुगूना हो जाने की संभावना है। 20 सुत्री कार्यक्रम के अधीन, वर्श 1985–86 के दोरान 300 मिनी डैरी यूनिटो के खोले

जाने का प्रस्ताव हैं। उपयूक्त स्कीमों पर कुल परिव्यय के 5 करोड रूपये से अधिक हो जाने की संभावना है।

सहकारिताए

कृशि के क्षेत्र मे ऋण तथा अन्य निविश्टो को सुगमता से उपलब्ध करवा कर और उपभोक्ता वस्तुओ की आपूर्ति आदि के द्वारा सहकारी समिमियां गांवो का नक ाा बदलने मे बहुत ही स ाक्त साधन सिद्व हुई है। सहकारी ऋण तथा सेवा–सिमितीयों और हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणो का लक्ष्य 1985–86 के लिए 255 करोड़ रूपये नि चत किया गया है। यह आ ाा की जाती है कि इस वर्श मे विपणन–समितियां 145 करोड़ रूपये का कृशि उत्पाद बेचने मे समर्थ हो सकेगी।

ग्रामीण रोजगार

ग्रामीण क्षेत्रो मे, बेकार श्रमिकों को वि ोशतः बेकारी के मौसम मे रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा स्थायी परिस्मपत्तियों का निर्माण करने के लिए राज्य मे राश्ट्रीय गांमीण रोजगार कार्यक्रम लागूं हैं। इस कार्यक्रम के लिये वर्श 1985–86 मे 5.1 करोड़ रूपये उपबन्ध किया गया है। गामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन, रोजगार योजनाओ पर और 4.2 करोड़ रूपये खर्च किए जाने के लिए प्रस्तावित है। इस से वर्श मे 11.46 लाख श्रम–दिन पैदा होगें।

11.00 बजे

उधोग

राज्य सरकार, उधोग को बढावा देने के लिए मूल ढांचे की विकसित करने हेतु निरन्तर प्रयास कर रही हैं। इस प्रयास को अगामी योजना–अवधि के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है। 9.6 करोड़ रूपये का योजनागत परिव्यय वर्श 1985–86 के दोरान उधोग के विकास केलिए प्रस्तावित है। राज्य मे लगाई जा रही बड़ी बड़ी परियोजनाओं मे से करनाल मे 1300 करोड़ रूपयेके पूजिगत परिव्यय से तेल ाोधक कारखाना तथा पंचकूला मे भारत इलैक्ट्रोनिक लिमिटिड द्वारा सीापित की जा रही 21 करोड़ रूपये की दूर–संचार –परियोजना है। हरियाणा मे रेलवे कोच–विनिर्माण फैक्टरी की सीापना का मामला भी काफी आगे बढ चुका है।

ओधोगिक विकास का बढावा देने के विचार से, राज्य सरकार द्वारा हाल ही मे वि ोश प्रोत्साहनो की घोशणा की गई हैं। इसके अतिरिक्त, प्रवर्त्तक, प्रतिश्ठित तथा भात प्रति ात निर्याताान्मुखी यूनिटो के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित ओधोगिक सहायता ग्रुप द्वारा किए गये प्रयतनों के परिणामस्वरूप 368 आ ाय–पत्र अनिवासी भारतीयों के पक्ष मे जारी किए जा चुकें हैं।

सड़के

सड़के विकास की धमनियां होती है। हरियाणा में पहले ही दे ा को सवोत्तम सड़क जाल बिछाा हुआ हैं, जो हमारे 98 प्रति ात से भी अधिक गांवो को जोड़ता है। तथापि, सड़कों के जाल को कार्यक्रम सातवी पंचवर्शीय योजना के दौरान भी जारी रखा जाना हैं। वर्श 1985–86 के लिए, सड़क निर्माण हेतु 15.5 करोड़ रूपये का उपबब्ध सड़को की लम्बाई 200 किलोमीटर तक और बढाने के लिए प्रस्तावित है।

ि ाक्षा

सरकार ि ा़क्षा को उच्च प्राथमिकता देती है और हम आगामी योजना–अवधि के दौरान भी ऐसा करते रहेगे। चालू वर्श के दौरान, 99 प्राथमिक विधालयों का दर्जा बढाकर उन्हे माध्यमिक विधालाय तथा 93 माध्यमिक विधालायों का दर्जा बढाकर उन्हे उच्च विधालय स्तर का बना दिया गया है। आगामी वर्श मे औरबहुत से प्राथमिक विधालयों तथाप माध्यमिक विधालयों का दर्जा बढा दिए जाने का प्रस्ताव है। मुफ्त वर्दी, लेखन सामग्री तथा उपस्थिति–छात्रवृत्तियों के रूप मे अनेक प्रोत्साहन भी दिए गए हैं। 29 संस्थानो मे 10+2 प्रणाली भी पहले से ही लागू कर दी गई है। और वर्श 1985–86 के दौरान 49 और संस्थांए इसके अन्तर्गत ले ली जाएंगी। विधालय तथा उच्चतर दोनों ही स्तरो पर लड़कियो की ि ाक्षा पर वि ोश बल दिया जा रहा है। प्रौढ ि ाक्षा कार्यक्रम न पर्याप्त प्रगति की है और इसे आगामी वर्श मे जारी रखे जाने का प्रस्ताव है, 21 करोड़ रूपए का योजना–परिव्यय

वर्श 1985–86 के दौरान ि ाक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के लिये रखने का प्रस्ताव है।

तकनिकी ि ाक्षा

तकनीकी ि ाक्षा के क्षेत्र मे उल्लेखनीय परियोजनाए है:– मुर्थर मे इंजीनियरिंग कालेज, हिसार मे इंजीनियरिंग तथा प्रोधोगिकी संस्था, सिरसा मे महिला पालिटैक्नीक तथा आदमपुर मे फार्मेसी तथा प्रबन्ध–संस्था की स्ाापना। इन परियोजनाओं के लिए वर्श 1985–86 के दौरान 3 करोड़ रूपयों के योजनागत आबटन का प्रस्ताव है।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं

राज्य सरकार चिकित्स, स्वास्थय तथा परिवार–कल्याण कार्य{मों के विस्तार को अत्याधिक प्राथमिकता देती है। चालू वित्त वर्श के अन्त तक 1600 उपकेन्द्र खोलने को लक्ष्य प्राप्त कर लेने की सम्भावना है। चालू वर्श के दौरान 8 हस्पतालों, 8 प्राथमिक स्वास्थ्य–केन्द्रो, 4 सहायक स्वास्थ्य केन्द्रो, एक ग्रामीण औशधालय और 390 उप केन्द्रो के भवन पूरे किए जा चुके हैं। कुरूक्षेत्र, पानीपत, जींद तथा कैथल के सामान्य हस्पतालों का दर्जा बढाकर 50 बिस्तर से 100 बिस्तर का कर दिया गया हैं। दो 25 बिस्तरो वाले हस्पताल सिवानी तथा हेली मण्डी मे स्ाापित किए गए हैं।

राज्य सरकार जनसंख्या को काबू मे रखने की आव यकता के प्रति भी सजग है, ताकि आर्थिक विकास के लाभ

लोगो को सचमुच उपलब्ध रहें। वर्श 1983–84 मे परिवार–कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी हमारी असाधारण उपलब्धि के लिए राज्या को भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ रूपए को पुरस्कार दिया गया हैं। चालू वर्श के दौरान जनवरी, 1985 के अन्त तक स्वैच्छिक आधार पर लगभग 59000 बन्धीकरण आपरे ान किए गए है। हमारे निरन्तर प्रयत्नों तथा लोगों के सक्रिय सहयोग से वर्श 1985 मे जन्म–दर के प्रति 35.6 प्रति 1000, से वर्श 1990 तक 28 प्रति 1000 तक कम हो जाने का अनुमार है। राज्या सरकार द्वारा वर्श 1985–86 के दौरान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य–सेवाए, जिसमे चिकित्सा–ि ाक्षा भी भाामिल हे, के विस्तार के लिए 13.55 करोड़ रूपए के योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव है।

आवास

आवास–सम्बन्धी समस्या पर भी राज्य सरकार का पूरा ध्यान रहा है। चालू वर्श के दौरान 3000 मकानो निर्माण–लक्ष्य से भी आगे बढ जाने की सम्भावना हैं। अगले वर्श के लिए आवास के लिए 7.29 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया हैं।

पेय जल आपूर्ति

पेयजल आपूर्ति लोगो को दी जाने वाली बुनियादी सुविधा हैं। चालू वर्श मे 800 गांवो को यह सुविधा देने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति सम्भावित है। वर्श 1985–86 के लिए जल आपूर्ति तथा मल–निकास योजनाओं के लिए 30 करोड़ रूपए

का योजनागत उपबन्ध करने का प्रस्ताव है। जिसमे लगभग 4 करोड़ रूपए भाहरी क्षेत्रों मे सफाई–सुविधाओ को सुधारने हेतू भाामिल है।

राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनो ही राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास पर अत्याधिक जोर दे रही हैं। हरियाणा का अधिक भाग इस क्षेत्र के समेकित विकास के लिए सााापित किया गया है। वर्श 1985–86 के लिए राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की कुछ स्कीमों को लागू करने के लिए 2 करोड़ रूपए के सांकेतिक उपबन्ध को प्रस्ताव है।

समाज के कमजोर वर्गो का उत्थान

वर्श 1985–86 के लिए 33 करोड़ रूपए से अधिक रा ि ा अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो के सदस्यों के कल्याण के लिए वि ोश संघटक योजना के तौर पर उपबन्धित करने का प्रस्ताव है। हमने वर्श के दौरान 55000 से अधिक परिवारों को वितीय सहायता देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। हरिजन–कल्याण–निगम तथा पिछड़े वर्ग–कल्याण–निगम इन जातियों के सदस्यों के आर्थिक स्थिती को उन्नत करने मे सहायता देने के लिए उदार योजनए चला रहे है। निर्धन, दुर्बल, भारिरिक रूप से विकलांग और नेत्रहीन आदि के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाए चल रही हैं। अगले वर्श के दौरान 10

करोड़ रूपए से अधिक का योजनागत परिव्यय समाज–कल्याण, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों और पोशाहार–कार्यक्रम के विस्तार के लिए रखने को प्रस्ताव है।

सैनिक तथा भूतपूर्व सैनिक

हरियाणा दे ा मे ऐसा पहला राज्या हैं जहां उन भूतपूर्व सैनिको ं को और भूतपूर्व सैनिको की विधवाओं को, जिनकी आयु 65 वर्श से अधिक है ओर जिन्हे किसी प्रकार की सेवा पें ान नही मिलती है 100 रूपए प्रतिमास के हिसाब से पें ान दी गई हैं। राज्या सरकार द्वारा पुनः नियूक्त किए गए भूतपूर्व सैनिको को दी जाने वाली एक अन्य रियायत 01.04.1979 के उनके वेतनमानों मे उपरिमुखी वेतन–नियतन किया जाना है। चालू वर्श के दौरान राज्या सरकार ने 'ब्ल्यू स्टार आपरे ान' मे मारे गए प्रत्येक अधिकारी के परिवार को 25000 रूपए कनिश्ट कमी ान प्राप्त अधिकारियों के मामल को 10000 रूपए दिए है। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिको के लिए अन्य अनेक सुविधाए दी जा रही है।

परिवहन

राज्या सरकार अपने लोगो के लिये एक कु ाल परिवहन की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्व है। आगामी वर्श की योजना मे 12 करोड़ रूपए के उपबन्ध का और हरियाणा रोड़वेज की बसों मे 150 और बसें जोड़ने का प्रस्ताव है।

दिल्ली–चण्डीगढ राजमांर्ग पर यातायात की जांच करने, कानून तथा व्यवस्था लागू करने तथा राजमार्ग पर दुर्घटना–ग्रस्त लोगो की सहायता करने के लिए लगभग प्रति 50 किलोमीटर के फासल पर पांच यातायात–सहायता–चौकियों की सीापना की गई हैं।

पर्यटन

वार्शिक योजना 1985–86 मे पयटर्न–सुविधाओं के विकास हेतू 1.8 करोड रूपए के परिव्यय का उपबन्ध है। अम्बाला मे किंगफि ार पर्यटक काम्पलैक्स का निर्माण–कार्य तेजी से चल रहा है और नरवाना तथा बहादूरगढ मे दो और काम्पलैक्सें का निर्माण–कार्य जल्दी ही भुरू होना संभावति है।

20 सूत्री कार्यक्रम

20 सुत्री कार्यक्रम राज्या सरकार द्वारा तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है वर्श 1985–86 के दौरान इस परियोजना के लिये 380 करोड़ रूपये के परिव्यय का उपबन्ध किया गया हैं। अप्रैल 1985 से जनवरी 1985 तक गरीबी कम करने वाली विभिन्न स्कीमों के अधी 65000 से अधिक परिवारों ने लाभ उठाया हैं जिनमे अनुसूचित जातियों के 33000 से भी अधिक परिवार भाामिल है। 10.32 लाख श्रम–दिनों का रोजगार बनाया गया है और 574 समस्या–ग्रामों के लिये पेयजल की व्यवस्था की गई हें इसी प्रकार इस अवधि मे 5060 मकानों के प्लाअ अलाट किए गए है। 90000 से अधिक व्यक्तियों को गंदी बस्ती सुधार स्कीमों

के अधीन लाभ पहुंचा है ओर 51 उचित मूल्य की दूकाने खोली गई हैं।

प्र ाासन तंत्र मे सुधार

प्र ाासनिक गुणो के विकास तथा राज्या के लक्ष्यों के बेहतर मूल्यांकन के लिए राज्या सरकार के कर्मचारियों को नए खोले गए हरियाणा लोक–प्र ाासन संस्थान मे प्र ि ाक्षण दिया जा रहा हैं। पुलिस बल के आधुनिकीकरण का काम भी भुरू किया गया है। सरकार हमारी परिवीक्षण–पद्धिती तथा प्रबन्ध सूचना प्रणाली मे सुधार के लिये भी जोर दे रही है। सूचना के अबाध तथा तुरन्त पारेशण तथा इसके वि लेशण के लिये इलैक्ट्रानिक तथा मकैनिकल यन्त्र की स्ाापना हेतू अगल वर्श के योजना बजट मे एक करोड़ रूपयों के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया हैं।

योजना–प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना–प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा हैं। राज्य सरकार भी यही महसूस करती है कि योजना बनाने का काम जहां तक संभव हो नीचे से भुरू होना चाहिए। नीचे से योजना बनाने की प्रकिया को तीव्र गति देने के लिये और क्षेत्र मे योजना म ाीनरी को मजबूत बनाने के लिये अगले वर्श के योजना बजट मे 15 करोड़ रूपयों से कुछ अधिक का उपबन्यध किया गया हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के विरूद्व संघर्श

विगत वर्श मे राज्या सरकार को कुछ भारी और अप्रथ्याि ात प्रतिकुलताओं का सामना करना पड़ा। सर्वाधिक जबरदस्त धक्का था पंजाब के इलाके मे भाखड़ा मुख्य नहर मे पड़ी दरारे जिनसे हमारी फसलों को जबदरस्त नुकसान पहुंचा और परिणामस्वरूप व्यापक हानि हुई। केन्द्रीय सरकार धन्यावाद की पात्र है कि दरारों केा जल्दी ही सफलता पूर्वक बन्द कर दिया गया। फिर भी, इनसे हमे भारी हानियां हुई और हमे किसानो को राहत देनी पड़ी जिसमे केन्द्रीय सरकार से अग्रिम केन्द्रीय सहायता के रूप मे प्राप्त 6.6 करोड़ रूपये भी भाामिल है। दूसरी बड़ी समस्या थी महेन्द्रगढ, भिवान, रोहतक, जीन्द तथा हिसार मे नमी–प्रकोप तथा जबरदस्त भीत लहर। हमारें किसानों के कश्टों को कम करने के लिये राज्य सरकार ने जोतकर तथा आबियाना की माफी के आदे ा दिये और किसानो को राहत के तौर पर 1. 55 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता भी दी। तीसरी आफत थी हमारे कपास–क्षेत्र मे कपास–ना ी कीड़ो के लग जाने के कारण कपास को हुआ नुकसान। इस मामले मे भी राज्य सरकार ने जोतकर तथा अबियाना माफ कर दिया और हानि–पीड़ित किसानों को 2.1 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता दी।

सरकारी कर्मचारियों तथा पैं ान भोगियों को दी गई सुविधाएं

विगत वर्श मे राज्या सरकार ने अपने कर्मचारियों को कई रियायतें तथा सुविधाए दी हैं। भारत सरकार की पद्धति पर

राज्या सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भते की 9 किस्तें स्वीकृत की गई है।

सरकारी कर्मचारी के लिए बेटे की भाादी की स्थिति मे विवाह–ऋण की सीमा 3000 रूपध्े से बढा कर 5000 रूपए तथा बेटी या बहन के विवाह की स्थिति मे 10000 रूपए कर दी है। बहन की भाादी के लिए ऐसा ऋण उस स्थिति मे भी दिया जाता है जबकि कर्मचारी के माता–पिता सौभाग्यवं ा जीवित हों।

कारों की खरीद के लिए ऋण की रा ि ा 40000 रूपए से बढा कर 60000 रूपए, दोपहिया वाहनों के लिए 6000 रूपए से 8000 रूपए तथा साइकलो के लिए 300 रूपए से बढा कर 400 रूपये कर दी गई हैं।

नेत्रहीन तथा भाारिरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए वाहन–भता 50 रूपए से बढा कर 75 रूपए प्रतिमास कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने भारत सरकार की पद्धिती–अनुसार ही एक समूह बीमा योजना भाुरू की है जिसके अन्तर्गत 10, 20, 40 तथा 80 रूपए प्रतिमास अभिदान करने पर राज्य सरकार के श्रेणी IV, III, II तथा I के कर्मचारियों का क्रम ाः 10000, 20000, 40000 तथा 80000 रूपए का बीमा हो जाता है। मुझे वि वास है कि इस योजना से हमारे कर्मचारियों को बहुत लाभ पहुंचेगां।

भारत सरकार की पद्धिती पर चालू वर्श के दौरान छुट्टी–यात्रा–रियायत की सुविधा भी दे दी गई है। आ ाा है, हमारे कर्मचारी इससे पूरा लाभ उठाएगें। यह योजना हमारी जनता को अधिक भावनात्मक एकता की ओर ले जाएगी।

1984–85 के सं ाोधित अनुमान तथा वार्शिक योजना

कुछ विपरीत स्थितीयों के कारण चालू वर्श की वित–वयवस्था पर अत्याधिक दबाव पड़ा हैं। वि ोश उल्लेखनीय देयता अतिरिक्त मंहगाई भते की किस्तो के काण, एक विपरित न्यायालय–निर्ण के कारण कुछ सौदों पर विक्री–कर की वसूली न हो पाना तथा पड़ोसी रात्या मे अ ाान्त परिस्थितियों के कारण हरियाणा मे राजस्वहानि होना है। इन प्रतिकलताओं के कारण चालू वर्श के 46.83 करोड़ रूपए के प्रथ्याि ात घाटे की तुलना मे 91.53 करोड़रूपए के घाटे के साथ समाप्त होने की आ ाा हैं। फिरप भी हमे आ ाा है कि इस घाटे का बड़ा हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा, जिए जाने वाले एक ऋण के रूपा मे बदल किया जाएगा।

1985–86 के लिए बजट–अनुमान तथा वार्शिक योजना

श्रीमान, अध्यक्ष महोदय, इस पृश्ठीाूमि मे, मै अब इस गरिमा ाली सदन के सामने बजट, अनुमान 1985–86 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वर्श 1984–85 के लियें सं ाोधित अनुमान तथा वर्श 1985–86 के लिए बजट–अनुमाने के अन्तर्गत इसके

बजट–सम्बन्धी लेन–देन के फलस्वरूप बनी राज्य की वितीय स्थिती निम्नलिखित आंकड़ो से परिलक्षित होती है:–

			(करोड रूपयों मे)
संघटक	बजट–अनुमान 184–85	सं ाोधित अनुमान 1984–85	बजट अनुमान 1985–85
1	2	3	4
(1) अथ भोश			
(क) महालेखाकार के अनुसार	(–)45.08	(–) 2.90	(–) 63.80
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(–) 50.53	(–) 30.63	(–)91.53
(2) राज्स्व लेखा			
प्राप्तियां	811.08	796.68	901.27
खर्च	683.65	748.13	828.77

अधि ेश	(+)127.43	(+)47.55	(+)72.50
(3) पूंजीगत खर्च (निवल)	130.08	128.53	184.15
(4) लोक ऋण			
लिया गया ऋण	568.09	644.71	700.45
अदायगी	505.17	553.71	615.93
निवल	(+)62.92	(+)91.60	(+)84.52
(5) कर्जे और पे ागियां			
पे ागियां	122.36	135.49	147.53
वसूलिया	28.15	30.45	22.87
निवल	(–)94.21	(–)105.04	(–)124.66
(6) अन्तर्राज्यीय निपटान	–	–	–
(7) आकस्मिक निधी (निवल)	–	–	–

(8) अनिधिक ऋण (निवल)	(+)26.55	(+)43.73	(+)29.65
(9) निक्षेप तथा पे ागियां आदि (निवल)	(+)06.09	(+)15.21	(+)95.05
(10) प्रेशण (निवल)	(+)5.00	(+)5.00	(+)4.00
(11) वर्श का इति ोश			
(क) महालेखाकार के अनुसार	(–)41.38	(–)63.80	(–)86.59
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(–)46.83	(–)91.53	(–)114.32

वर्श 1985–86 के लिए बजट–प्रस्तावों की सकारात्मक वि ोशताओं मे से एक वि ोशता राज्य–लेखे पर अधिक प्राप्तियां और इनके परिणामस्वरूप ज्यादा राज्सवअधि ोश है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व–अधि ोश के चालू वर्श के 47.55 करोड़ रूपए से बढकर आगामी वश्र मे 72.5 करोड़ रूपए तक हो

जाने की सम्भावना है। दूसरी वर्णनीय वि ोशता, अगामी वर्श के लियो प्रस्तावित योजना आकार मे उल्लेखनीय वृद्वि है जिसके 500 करोड़ रूपए की काफी बढ जाने की सम्भावना है। राज्य की 1985–86 की वार्शिक योजना और सातवी योजना की संभावना है। राज्या की 1985–86 की वार्शिक योजना और सातवी योजनाके आकार पर भारत सरकार के साथ अन्तिम चरण का विचार विम र्ा आगामी मास के किसी समय किया जाएगा। इस विचार विर्म ा आगामी मास के किसी समय किया जाएगा। इस विचार विम र्ा के दौरान इस परिव्यय का निर्धारण अन्तिक रूप से कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विगत वर्श मे केन्द्र–प्रायोजित योजनाओ और अन्य विकास योजनाओ, जो राजय योजना का भाग नही है, पर 65 करोड़ रूपयों से अधिक खर्च होने की संभावना हैं। अगले वर्श मे इस प्रयोजन के लिये 68.26 करोड़ रूपयो के उपबन्ध का प्रस्ताव है।

बजट–संबन्धी घाटे को पूरा करने के उपाय

जैसा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत वर्श 1985–86 के बजट अनुमाने से पता चलता हैं वर्श के लिये 114.32 करोड़ रूपये को इति ोश परिकल्पित है। संसाधनो मे इस अन्तर को कुछ वि ोश तरीकों मे पूरा करने का प्रस्ताव है। सर्वप्रथम, जैसा कि मैने पहले बताया है कि हमने सतलुत–यमुना–संपर्क–परियोजना के लिये वि ोश सहायात हेतू केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। आगामी वर्श के लिये इस परियोजना हेतू योजनागत आंबटन 70

करोड़ रूपये हैं यदि भारत सरकार हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है तो हमारे संसाधनों पर भार तदनुसार कम हो जाएगा।

परेशण–कर

एक ओर बड़ा उपाय जो इस अन्तर का पूरा करेगा, परेशण कर अगाहना है जिसके लिये संविधान पहले से ही सं ाोधित है। संसद द्वारा अब सक्रियात्मक कानून अधिनियमित किया जाना हैं। हम आ ाा करते है कि यह बहुत जल्दी होगा जैसा कि भारत सरकार द्वारा आरूवासन दिया गया है। यदि परेशण–कर पूरे वर्श उपल्बध होत हो हमे आ ाा है कि अगामी वर्श मे लगभग 44.5 करोड़ रूपया इक्ट्ठा हो जाएगा।

अतिरिक्त कराधान के लिए प्रस्ताव

हरियाणा रोडवेज की परिचालन– लागत मे अनेक कारणो, जिनमे डीजल तथा अन्या पेट्रोलियम–उत्पादों मे मूल्य वृद्वि भी भाामिल है से हुई वृद्वि को निश्क्रिय करने के लिय पक्की सड़क से यात्रा मे साधारण बसों का किराया 01.04.1985 से 1.25 पैसे प्रति किलोमीटर बढाने का प्रस्ताव हैं। अन्य प्रकार से बस किरायो मे से एक अनुपातिक वृद्वि भी प्रस्तावित है। आगामी वर्श मे इस उपाय से लगभग 15 करोड़ रूपये मिल जाने की सम्भावना हैं। यात्री–कर–प्राप्तियों मे ओर 9 करोड़ रूपये की परिणामी वृद्वि हो जाएगी।

सरकार ने बस–किराए को युक्ति–संगत बनाने का निर्णय भी लिया है जिससे न्यूनतम किराया 50 पैसे हो जाएगा। अगले 50 पैसों के लियें भी जबकि 24 पैसे या कम किराये को छोड़ दिया जाएगा, 25 पैसा या इससे अधिक को 50 पैसे मान लिया जायेगा। तथापि इस तरह युक्ति–संगत– बनाने से कुल यातायात–प्राप्तियां किसी भी प्रकार से बहुत अधिक प्रभावित नही होगी।

इस समय सार्वजनिक माल–वाहनों पर माल–कर 2000 रूपये वार्शिक दर पर वसूल किया जा रहा है। सरकार का इसे 01.04.1985 से 2400 रूपये वार्शिक तक बढान का प्रस्ताव है। इस उपाय से दो करोड़ रूपये के अतिरिक्त राजस्व के मिलने की सम्भावना हैं।

राज्य सरकार ने भाराब तथा भाराब की दूकानों पर भाुल्क तथा फीसें बढाने का भी निर्णया किया है। भारत मे बनाई गई विदे ाी स्पिरिट पर आबकारी– ाुल्क 32 रूपये से बढाकर 36 रूपये प्रति प्रूफ लीटर कर दिया गया है। भाराब तथा आ ाोधित स्पिरिट पर निर्यात फीस 1 रूपये से बढाकर 3 रूपये प्रति प्रुफ लीटर कर दी गई है, परिवर्तित स्पिरिट पर निर्यात–फीस 1 रूपये से बढाकर 3 रूपये प्रति बल्क लीटर कर दी गई हें इसके अतिरिक्त बीयर पर 50 पैसो प्रति बोतल निर्यात–फीस लगाई गई है यै उपाय वर्श 1985–86 की नई आबकार–नीति का एक भाग है ओर इससे अगले वर्श के दौरान 10 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राजस्व–प्राप्ति की सम्भावना हैं।

बिजली–उत्पादन पर संघ–उत्पादन– ाुल्क 01.10.1984 से हटा दिया गया हैं। उत्पादन– ाुल्क को हटाये जाने से हुई कमी को पूरा करने के लिए घरेलू, वाणिज्यिक तथा औधोगिक उपभोक्ताऔ पर क्रम ाः 2,3,4 पैसे प्रति युनिट के हिसाब से 01. 04.1985 से बिजली– ाुल्क मे वृद्वि करने का प्रस्ताव है। फिर भी उपभोक्ताओं से ली जाने वाली रा ियों मे इसके कारण कोई वृद्वि नही होगी क्योकि टैरिफ दरें आदि नियत करते समय संघ–उत्पादन– ाुल्क को पहले ही भाामिल कर लिया गया था। उक्त आधार पर बिजली– ाुल्क मे वृद्वि से राज्य सरकार को लगभग 6 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा।

उक्त उपायों से हमे अगल वर्श लगभग 86.5 करोड़ रूपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। यह उपाय तथा सतलुज–यमुना–सपंर्क–परियोजना के लिए संभावित वि ोश केन्द्रीय सहायता, राज्य–योजना के लिये केन्द्रीय सहायता मे और बाजार ऋणों मे हमारा अधिक हिस्सा, अगले साल के 114.32 करोड़ के प्रत्या ित अन्तिम घाटे को पूरा करने मे सहायक सिद्वा हो जाने चाहियें।

सरकारी कर्मचारियों तथा अन्यो को अतिरिक्त सुविधाए

यहा इस बात का जिक्र करना भी उचित होगा कि हम सरकार कर्मचारियों तथा अनें को अतिरिक्त सुविधाए तथा रियायते देने का प्रस्ताव करते है।

सरकारने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 01.04. 1985 से समूह–बीमा योजना मे 10 रूपये प्रतिमास का अं ादान करने को निर्णय लिया है। इसकी देयता लगभग 50 लाख रूपये प्रतिवर्श बनेगी।

यह निर्णय भी लिया गया है कि श्रेणी III तथा श्रेणी IV के किसी भी कर्मचारी की सेवावधि के दोरान मृत्यू हो जाने की स्थिति मे उसके गृह–निर्माण ऋण, विवाह–ऋण, गेहू–ऋण तथा साईकल–ऋण की बाकाया मूल रकम माफ कर दी जाएगी। (तालियां) सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि श्रेणी III तथा IV के ऐसे कर्मचारियों द्वारा लिये गये सभी ऋणों पर बकाया ब्याज की वसूली भी छोड़ दी जाएगी। किन्तु गृह निर्माण ऋण के मामले की बकाया रकम केवल उन्ही मामलों मे काफ की जाएगी जहां परिवार के पीछे बचे सदस्यो मे से एक अधिक नौकरी मे नही हो।

सरकार ने निर्णय लिया है कि 01.04.1985 से चण्डीगढ मे नगर प्रतिकर–भते की सीमा 100 रूपये की वर्तमान सीमा के भीतर ही रहते हुए 8 प्रति ात से 10 प्रति ात कर दी जाएगी। इस राहत से राज्य पर लगभग 18 लाख रूपए वार्शिक का भार पड़ेगा। इस समय नग–प्रतिकर भता चण्डीगढ के अतिरिक्त अन्य ऐसे नगरो मे मिलता है जहां कि जनसंख्या एक लाख या इससे अधिक है और क्षेत्र 30 वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक है। गुडगांव, भिवानी, पानीपत, सोनीपत तथा करनाल–पांच कस्बों की जनसंख्या तो 1981 की गणना के अनुसार एक लाख से अधिक है

किन्तु इनका क्षेत्र 30 वर्ग किलोमीटर से कम पड़ता है इन कस्बों मे नियुक्त सरकारी कर्मचारी की कठिनाईयों को समझते हुए ओर उन्हे राहत पहुंचान के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इन पाचों नगरो मे काम करने वाले कर्मचारियों को भी 01.04.1985 से 50 रूपए की सीमा मे 5 प्रति ात की दर से नगर–प्रतिकर–भता दूसरो नगरों की भांति ही स्वीकार्य होगा। (तालिया) इससे राज्य पर लगभग 75 लाख रूपए प्रतिवर्श का भार पड़ेगा।

अभी सिविल सचिवालय मे काम कर रहे चालकों के लिए वि ोश वेतन स्वीकार्य है। अन्य कार्यालयों के चालको की कठिनाईयों को स्वीकार करते हुए सरकार ने दूसरे चालकों को भी 01.04.1985 से वि ोश वेतन देने का निर्णय किया हैं। यह निर्णया किया गया है कि विभागध्यक्षों के कार्यालयों मे कार्यरत चालको को 100 रूपए तथा दूसरे क्षेत्रीय कार्यलायों के चालको को 50 रूपए प्रतिमास को वि ोश वेतन स्वीकार्य होगा। उनको स्वीकार्य अतिसमय भता वाापिस लिया जा रहा है।

01.04.1979 से सं ाोधित वेतनमानों को लागू करते समय सरकार ने कुछ वि ोश श्रेणियों द्वारा प्राप्त किए जानो वाले वि ोश वेतनो तथा नान प्रक्टिसिंग भते की उपरिसीमा निर्धारित करने को निर्णया लिया था। राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के मामले मे यह उपरिसीमा पहले ही हटाई जा चुकी हैं। सरकार ने 01.04.1985 से इस उपरिसीमा को अब डाक्टरों के मामले मे भी हटाने को निर्णया लिया हैं।

व्यापार, उधाग तथा कृशि के लिए रियायतें।

(I) सरकार ने बिक्री कर निर्धारण हेतू निर्माता व्यापारियों के मामलों मे टर्न–ओवर–सीमा 25000 रूपयेसे बढाकर 1 लाख रूपए प्रतिवर्श करने का निर्णय लिया है। (तालियां) विधान सभा के वर्तमान सत्र मे इस सं ाोधन के लिये बिल प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है;

(II) सरकार ने ढाबेवालों और तन्दूरवालों आदि पर बिक्री–कर की छूट को बहाल करने को निर्णय लिया है। (तालियां) यह छूट भी विधान सभा के वर्तमान सत्र मे विचारर्थ प्रस्तुत किये जाने वाले बिल का भाग होगी;

(III) लेखन–सामग्री–आपूर्ति–कर्ताओ की कठिनाईयों को अनुभव करते हुए तथा छात्रो के हितो मे सरकार ने सिक्केवाल पैंसिलों का 01.04.1985 के विक्री कर से छूट देने का निर्णय लिया है;

(IV) भारतीय महिलाओ द्वारा व्यापक रूप से पहली जाने वाली कांच की चूड़ियो पर बिक्रीकर कम करने की मांग बड़ी देर से चली आ रही है। सरकार ने कांच की चूडियों पर बिक्रीकर की दर को 01.04.1985 से 12प्रति ात से 4 प्रति ात करने का निर्णय लिया है। (तालियां)

(V) 20 सुत्री कार्यक्रम के अधीन बायेगैंस–उपकरण को प्रोत्साहन देने पर वि ोश बल दिया गया है। ऊर्जा के संरक्षण की

आव यता को स्वीकार करते हुए ओर बैकल्पिक ऊर्जा–स्त्रोतों का दोहन करने के लिए राज्य सरकार ने 01.04.1985 से बनरों के अतिरिक्त सभी बायोगैंस–उपकरणों पर बिक्रीकर माफ करने का निर्णया लिया है;(तालियां) तथा

(VI) खेतीहार–समुदाय की ओर से कृशि–निविश्टों की लागत कम करने की मांग निरन्तर चली आ रही हैं। सरकार ने 01.04.1985 से कृशि–प्रयोजनों के लिये प्रयूक्त होने वाले 7.5 हार्स–पावर क्षमता तक के मोनो–ब्लाक–पंपिंग सैंटो पर बिक्री–कर छूट देने का निर्णया लिया है। (तालियां)

इन रियायतो से राजस्व मे होने वाला कुल घाटा लगभग 50 लाख रूपए वार्शिक होगा। इससे होने वाली व्यापक राहत से दृश्टिगत ये राहते पूरी तरह से न्याय–संगत प्रतीत होती है। फिर भी, राजस्व मे होने वाले घाटे को करों के बेहतर संग्रह से पूरा कर लिया जाऐगा।

व्यापरी समुदाय को राहत देनेके लिए और उन की चिरकालीन मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने विभिन्न आव यक वस्तुओ को कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए लाईसैसों की संख्या कम से कम करेन को निर्णय लिया हैं। इस निर्णया के तुरन्त अनुपाल के लिए खाध एवं आपूर्ति विभाग को निर्दे ा दे दिए गए हैं।

हरियाणा खाधान्न व्यापारी लाईसैंसिंग तथा मूल्य नियंत्रण आदे ा 1978 के अधीन खाधान्न लाईसैंसधारियों द्वारा गेहूं की भण्डारण–सीमा चक्कियों के मामाले मे 150 क्विंटल से बढा कर 300 क्विंटल और खाधान्न व्यापारियों के मामले मे 250 क्विंटल से बढाकरा 500 क्विंटल कर दी गई है।

इसके साथ, मै अपना बजट–भाशण, जो संभवत मेरे मान्य साथियों के लिए काफी कश्टकर रहा होगा, समाप्त कर रहा हूं। मै आप सब का और धैर्यपूर्वक मूझे सुनते रहे है।

भाशण समाप्त करने से पूर्व मै वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होने इन अनुमानो को तैयार करने मे अमूल्य सहायता दी है। मै इस सम्बन्ध से सहायता देने के लिए महालेखाकार, हरियाणा का तथा इन दस्तोवेजो का समय पर छापने के लिए संघ–क्षेत्र–प्र ाासन ओर हरियाणा मुद्रणालय का भी धन्यवादी हूं।

महोदय, इन भाब्दों के साथ अब मै वर्श 1985–86 के बजट–अनुमानों को गारिमा ाली सदन के विचार तााि अनुमोदक हेतू प्रस्तुत करता हूं। (तालियां)

जय हिन्द

WALK-OUT

During the course of the presentation of the Budget 1985-86 by the Finance Minister, all the member of the

Opposition stated a walk out as a protest against the proposed increase in electricity duty on different categories of sconsumers.

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

11.27 बजे

(तत्प चात सदन वीरवार, दिनांक 21.03.1985 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)

ANNEXURE

Provision of double Link Roads.

***936 Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state whether the facility of double Link roads has been provided in any of the Villages in the state; if so, the constituency wise names of such village?

Public Works Minister (Sh. Amar Singh):

Yes. A statement showing the names of villages provided with facility of double link roads in each constituency is attached herewith.

STATEMENT

Statement Showing Constituency wise detail of villages provided with facility of double link roads upto 28.02.1985

Sr. No.	Name of Constituency	Sr. No.	Name of Villages
Ambala District			
1.	Kalka	1.	Khatauli
		2	Nangal
2	Naraingarh	1	Ganauli
		2	Mandli
		3	Bhood

		4	Hassaini
		5	Nai Gaon
		6	Raiwali
		7	Bari Berhri
		8	Badhauli
3	Sadhura	1.	Makhaur
		2	Gainwala
4	Chhachrauli	1	Rattanpur
		2	Bahrampur
		3	Bakarpur
		4	Mukharmpur
		5	Dadupaura
		6	Chhachrauli
		7	Amadalpour
5	Jagadhri	1	Hangoli
		2	Sailba
		3	jharchandana
		4	Jandhera
		5	Guglaon

		6	Kalawar
		7	Azizpur
		8	Jagadhauli
6	Yamuna Nagar		-
7	Mullana	1	Tangali
		2	Dhanura
		3	Mullana
		4	Jharumajra
		5	Sohana
		6	Bhita
		7	Ghastipur
8	Ambala Cantt.		-
9	Ambala City		-
10	Nanagl	1	Nanhera
		2	Ahma
		3	Quarbanpur
		4	Bara
		5	Tharwa
		6	Babaheri

		7	Kotkatchwa Kalan
		8	Barauala
		9	Barauli
Karnal District			
11	Indri	1	Uchana
		2	Gheer
		3	Mohdeenpur
		4	Gumthala Rao
		5	Chugaon
		6	Biyana
		7	Baragaon
		8	Lendhera
		9	Malkali
		10	Kairk Jagir
12	Nilokheri	1	Bhola Khalsa
		2	Gholpur
		3	Naraina
		4	Birnaraina
		5	Lilani

		6	Tarori
		7	Keor
		8	Bir Badwla
		9	Segga
		10	Raison
13	Karnal	1	Bazida Jattan
		2	Bhusli
		3	Kurk
		4	Jatpura
14	Jundla	1	Uplana
		2	Uplani
		3	Rattak
		4	Jani
		5	Budhanpur
		6	Zarifabad
		7	Kachwa
		8	Bhojpur
		9	Sambli
		10	Nissing

		11	Gonder
		12	Saori
		13	Katleheri
		14	Alipur Viran
		15	Karsa Chaor
		16	Dachar
		17	Sheikhpura
		18	Anchala
		19	Balrangara
		20	Brass
		21	Siramai
15	Ghraunda	1	Arainpura
		2	Choura
		3	Badarpur
		4	Rajapur
		5	Ganjhar
		6	Upli
		7	Gianpura
		8	Sohana

		9	Rasulpur
		10	Modipur
		11	Dhakwala
		12	Mamoodpur
		13	Bazidpur
		14	Jsurali Khurd
		15	Ranwar
		16	Palheri Harsinghpura
		17	Garhi Khajoor
		18	Kaimla
		19	Kalheri
		20	Jarauli
		21	Jamalpur
		22	Bhaumajra
		23	Kutaili
		24	Pipalwali
		25	Kairwal
		26	Ucha Samana
		27	Ganjhogarhi

		28	Malikpur Gadian
		29	Kalron
		30	Basdhara
		31	Gianpura
		32	Amiritpura Kalan
		33	Barana
		34	Malikpur
		35	Sheikhpura
		36	Rasin
		37	Rasulpur
		38	Chundipur
		39	Harsinghpur
		40	Sharifabad
		41	Dabarki.
16	Assandh	1	Rear Kalan
		2	Kawi
		3	Malikpur
		4	Pabbban Hassanpur
		5	Mohamadpur

		6	Dharamagarh
		7	Thirana
		8	Madluda
		9	Joshi
		10	Ahmedpur Majra
		11	Rajapur
		12	Kachroli
		13	Assan Kalan
		14	Assand
17	Panipat		-
18	Samalkha	1	Dadola
		2	Dadoli
		3	Rishpur
		4	Bapoli
		5	Nagla
		6	Babail
		7	Nahehra
		8	Ujha
		9	Udmi

		10	Jalmana
		11	Bhalapura
		12	Sangoli
		13	Simla Gujran
		14	Jalapur
		15	Beholi
		16	Raimal
		17	Naraina
		18	Bharpra
		19	Manana
		20	Mohati
		21	Dehra
		22	Atta
		23	Peonti
		24	Hathwala
		25	Budhanpur
		26	Rakshera
		27	Ferozpur
		28	Chulkana

19	Naultha	1	Kakoda
		2	Urlana
		3	Damyana
		4	Seenk
		5	Diwan
		6	Siwah
		7	Sutana
		8	Brahman Majra
		9	Jondhan Kalan
		10	Khard
		11	Bhaupur
		12	Nain
		13	Alupur
		14	Kalha
		15	Lorhari
		16	Bursham
		17	Didwari
		18	Balana
		19	Pajheri

		20	Chmrara
		21	Bandh
		22	Mandi
		23	Gawalra
		24	Puthar
		25	Bhandari
		26	Daryapur
		27	Assan Khurad
		28	Kutani
		29	Urlana Khurd
		30	Kurana
Kurukshetra District			
20	Shahbad	1	Kurari
		2	Tangora
21	Radaur	1	Jabndoula
		2	Sangour
		3	Lakhmari
		4	Behawi
		5	Ram Nagar

		6	Bhagwanpur
		7	Koula Pur
		8	Mereheri
		9	Kalwa
		10	Birthala
		11	Dudla
		12	Marthala
		13	Kandroli
		14	Gumthala
		15	Bandi Nangala
		16	Sadian
		17	Jaguri
		18	Mehra
		19	Shahazdpur
22	Thanesar	1	Kheri Gadain
		2	Karanmi
		3	Mirzapur
23	Pehowa	1	Duldahera
		2	Goledewa

24	Gulha	1	Milikpur
		2	Ferozpur
25	Kaithal	1	khanpur
		2	Khurana
		3	Geong
		4	Teak
		5	Keorak
		6	Berout
26	Pundri	1	Sirsa
		2	Pindarsi
		3	Pabnawa
		4	Chandlana
		5	Habri
		6	Bagpur
		7	Khamoda
		8	Jandola
		9	Solumajra
		10	Bandarna
		11	Pharal

		12	Kaul
		13	Sakra
		14	Teontha
		15	Fatehpur
		16	Hajwana
		17	Sirsal
		18	Achhanpur
		19	Rasulur
		20	Deeg
27	Pai	1	Pai
		2	Harsola
		3	Jakhouli
		4	Kassan
		5	Rehra
		6	Bakkal
		7	Khanouda
		8	Sherda
		9	Rewanhera
		10	Kotara

		11	Sega
Rohtak District			
28	Haseanpur	1	Morkheri
		2	Kansala
		3	Baliana
		4	Paksama
		5	Kasranti
29	Kiloi		-
30	Rohtak		-
31	Meham		-
32	Kalanaur	1	Nigana
		2	Katesra
		3	Ballb
		4	Timarpur
		5	Patwarpur
		6	Garhi Ballab
		7	Kahnaur
		8	Pilana
		9	Maniha

33	Beri	1	Beri
		2	Dhaur
		3	Kabulpour
		4	Chimni
		5	Dhurana
		6	Majra
		7	Malipur
34	Sahlawans		-
35	Jhajjar	1	Kijrodh
		2	Salodha
		3	Orangpur
		4	Zahidpur
36	Badli	1	Kharman
		2	Dulhera
		3	Kakrala
		4	Munipur
		5	Pelpa
		6	Sohdhi
		7	Khungai

37	Bahadurgarh	1	Kulassi
		2	Jassaurkeri
		3	Ladrawa
		4	Sidipur
		5	Gubana
		6	Parnala
		7	Khairpur
		8	Kanoda
Sonepat District			
38	Baroda	1	Madina
		2	Chhichrana
		3	Jagsi
		4	Gangana
		5	Kohla
		6	Gharwal
39	Gohana	1	Bajana Khurd
		2	Samri
		3	Rolad Latipur
		4	Saragthal

40	Kailana	1	Teori
		2	Atail
		3	Bhora
		4	Lalheri
		5	Larsoli
		6	Shahpur Turk
41	Sonepat	1	Karewari
		2	Juon
42	Rai	1	Bharia
		2	Baquipur
		3	Khurampur
		4	Mohamdabad
43	Rohat	1	Bhatgaon
		2	Rattangarh
		3	Halalpur
		4	jaanjoli
		5	Jasrana
		6	Rarmana
		7	Mandora

Jind District			
44	Kalayat	1	Haripura
		2	Sanghan
		3	Gurthali
		4	Bhana Brahaman
		5	Lodha
		6	Sudkain Khurd
		7	Nakhalgarh
45	Narwana	1	Dhamtan
		2	Bhullan
		3	Khardwal
		4	Samain
		5	Dhabi Tak Singh
		6	Gulehri
		7	Rashidon
		8	Padarth Khera
		9	Badowal
		10	Dablan
		11	Barta

		12	Dhanuri
46	Uchana	1	Khakroda
		2	Surbrah
		3	Gogrian
		4	Kasohan
47	Rajaund	1	Rajaund
		2	Kithana
48	Jind	1	Pindara
		2	Kheri Taloda
		3	Dhatrath
49	Julana		-
50	Safidon		-
Faridabad District			
51	Faridabad		-
52	Meola Maharajpur	1	Badshapur
		2	Dalelpur
		3	Badkhal
		4	Arangpur
		5	Shahbad

		6	Bhuapur
		7	Bhansrali
		8	Fattupura
53	Ballabghar	1	Gharora
		2	Chandpur
		3	Manokol
		4	Behbalpur
		5	Ladauli
		6	Sadarpur
		7	Aterna
		8	Punhana Kalan
		9	Punhera Khurd
		10	Matuka
		11	Garkhera
54	Palwal		-
55	Hasanpur	1	Paingalthu
		2	Khambi
56	Hathin	1	Pahari
		2	Bahin

		3	Sondh
		4	Anohop
		5	Bamnola
		6	Jogi
		7	Tikri Brahman
		8	Khilluka
		9	Kot
		10	Alimeo Pasar
		11	Manpur
Gurgaon District			
57	Gerzepur Jhirka	1	Papra
		2	Papri
		3	Akbarpur
		4	Manu
		5	Tigaon
58	Nuh	1	Dhana
		2	Ter
		3	Suiltanpur
		4	Punhana

		5	Karhera
		6	Nagian Sarauli
		7	Maluka
59	Taoru	1	Sabgras
		2	Hassanpur
		3	Khaupur Badlaki
		4	Sarsai
		5	Kota Khandevia
		6	Ujjin
		7	Karika
		8	Barka
		9	Alimmudin
60	Sohana		-
61	Gurgoan	1	Darterpuri
		2	Chooma
62	Pataudi	1	Fezelpur
		2	Badli
		3	Daboda
		4	Bisulda

		5	Duman Dadawa
Bhiwani District			
63	Badhra	1	Jewali
		2	Barla
		3	Bodrai
		4	Unn
		5	Mai Kalna
		6	Dudhiwala
61	Dadri	1	Dudiwala
		2	Kishanpur
		3	Golpoura
		4	Chappoar
		5	Rasiwas
		6	Mehra
		7	Achina Sarupgarh
65	Mundhal	1	Mithathali
		2	Gujranai
		3	Ghukani
		4	Nathuwas

		5	Balyali
		6	Sui
		7	Talu
		8	Sankror
66	Bhiwani	1	Manheru
		2	Goripur
		3	Pehladgarh
		4	Dhana Narsan
		5	Paluwas
67	Tosham	1	Garanpur Purana
		2	Chhappar
		3	Jogian
		4	Garanpura Naya
		5	Badlwala
		6	Dadam
		7	Rewasa
		8	Dahni Mahu
		9	Endiwali
		10	Dhab Dhani

		11	Khariwas
		12	Sungerpur
		13	Similiwas
		14	Mansarwas
		15	Daryapur
		16	Bagwanwala
		17	Dinod
		18	Devsar
		19	Nigana Kalan
		20	Khawa
		21	Jhulli
		22	Ghariwas
		23	Sahewala
		24	Sasan Sagwan
68	Loharu	1	Kalod
		2	Amirwas
		3	Jarwa
		4	Shampura
		5	Basri

		6	Satnali
		7	Birsingwas
69	Bawani Khera	1	Siwara
		2	Khungar
		3	Ratera
		4	Rupana
		5	Talwandi Badshapura
		6	Bohal
Hissar District			
70	Barwala	1	Durajanpura
		2	Lkatani
		3	Khurkara
		4	Prbhuwala
71	Narnaund	1	Bad Chhapper
		2	Datta
		3	Gurana
		4	Petwar
		5	Sisai
		6	Lohari

72	Hansi	1	Sisar
		2	Kharbala
		3	Dhanderi
		4	Ramayan
73	Bhattu Kalan	1	Jeora
		2	Shamsukh
		3	Kirara
		4	Nangthela
		5	Landhri
		6	Kirmara
		7	Kanoh
		8	Anshrawa
		9	Sulikhera
		10	Sheikhupra Daroli
		11	Banawali
		12	Chiberwal
		13	Daroli
		14	Chuli Kalan
		15	Bhodia Khera

		16	Sadalpour
		17	Shuli Bagrain
		18	Chinder
		19	Sarangpur
		20	Khasa Maljajan
		21	Kharakheri
		22	Badopal
		23	Gadli
		24	Chuli Khurd
		25	Kalirawan
74	Hissar		-
75	Ghirai	1	Ladwa
		2	Pabra
		3	Daulatpur
		4	Bhatla
		5	Mahjid
76	Tohana	1	Damokra
		2	Nagla
		3	Salimpuri

77	Ratia	1	Jakhal
		2	Razanwali
78	Fatehabad	1	Banawali
		2	Bighar
		3	Dhanger
		4	Dahani Majra
		5	Mahamadpur Rohi
		6	Khajuri Jatti
		7	Badopal
		8	Jahalania
		9	Palsar
		10	Sehnal
		11	Alisadar
		12	Harzrawan Khurd
79	Adampur	1	Ladvi
		2	Sundawas
		3	Kharia
		4	Kohli
		5	Kabrel

		6	Dobhi
		7	Mingikhera
		8	Kirtan
		9	Shahpur
		10	Mlapur
		11	Neoli Khurd
		12	Ralwas Khurd
		13	Siswala
		14	Ranlwas Kalan
		15	Panihar
		16	Patan
		17	Tokas
		18	Kuri
		19	Ludas
		20	Gorchi
		21	Mahbatpur
		22	Malahsara
		23	Neoli Khurd
		24	Ghursal

		25	Kufia Kheri
		26	Bandaheri
		27	Singhran
Sirsa District			
80	Darba Kalan	1	Gillan Khera
		2	Baodiwali
		3	Jandwala
		4	Mangala
		5	Tatukhera
		6	Sahkkar Mandori
		7	Rampura Bish
81	Ellanabad	1	Rania
		2	Sultanpuria
		3	Kariwala
		4	Bani
		5	Mithi Surera
		6	Khari Surera
		7	Mamera
		8	Mangalia

		9	Kharia
		10	Ottu
		11	Maujdeen
82	Sirsa	1	Baruwali Ist
		2	Bharokhan
83	Rodi	1	Raisalkhera
		2	Barwala
		3	Khaishergarh
		4	Jhiri
		5	Bhunna
		6	Kharia
		7	Bhunna
		8	Kharia
		9	Mahankhera
		10	Chakan
		11	Kherwala
		12	Rampura Bishoian
		13	Nuhiyahnwali
		14	Odhan

		15	Ghokanwali
		16	Anandgarh
		17	Lakkarwali
		18	Panjmala
		19	Jhorar Rohi
		20	Thiraj
		21	Bhiwan
		22	Daulatpur
		23	Lakkarwarli
		24	Subukhera
		25	Sukhchain
84	Dabwali	1	Khokkar
		2	Naurang
		3	P(hullo
		4	Chitha
		5	Ganga
		6	Jandwala
		7	Bishlan
		8	Gobindgarh

		9	Rajpura
		10	Assakhera
		11	Tejakhera
		12	Sukherakera
		13	Ahamdpur
		14	Dareala
Mohindergarh District			
85	Bawal	1	Pithanwas
		2	Daliaki
		3	Bhandore
		4	Banipur
		5	Pathuhera
		6	Kheri Dalusingh
		7	Rassiawas
86	Rewari	1	Padniwas
		2	Majra Gurdas
		3	Sangwari
		4	Balawasbir
		5	Bhudpur

		6	Gokalpur
87	Jatusana	1	Basboda
		2	Kulan
		3	Aulant
		4	Mutlakhurd
		5	Lisan
		6	Uchat
		7	Bhagot
		8	Dhanunda
		9	Jhararli
		10	Mori
		11	Bhoka
88	Mohindergarh	1	Pora
		2	Notana
		3	Bhjanore Unchi
		4	Bhalkhi
		5	Nimbi
		6	Chajiwas
		7	Kharoli

89	Ateli	1	Salarpur
		2	Kalwari
		3	Dublana
		4	Kamania
		5	Chapora Bibpur
		6	Kharana
		7	Kharani
90	Narnaul	1	Punchuota
		2	Massuota
		3	Thanwas
		4	Lultajpur
		5	Hassanpur
		6	Maroli
		7	Dholera
		8	Magat Binja